सितंबर 2022
खंड - XXXVIII | अंक - III

एक्ज़िमिअस: निर्यात लाभ

इस अंक में

- भारत में सृजनात्मक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन
- एक लचीले अफ्रीका का निर्माण: भारत की बढ़ी हुई भूमिका
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर रूस-यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव
- एक संतुलित भारत-यूरोपीय संघ एफटीए की ओर
- भारत का इंजीनियरिंग वस्तु क्षेत्र : अद्यतन स्थिति

तिमाही प्रकाशन

इंडिया एक्ज़िम बैंक

केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई - 400 005.
फोन: 022 2217 2600
ईमेल: ccg@eximbankindia.in
www.eximbankindia.in
www.eximmitra.in

भारत में सृजनात्मक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन

सृजनात्मक उद्योग मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन तत्वों में से एक है; हालांकि, शब्द `रचनात्मक उद्योग' किसी एक परिभाषा से बंधा नहीं है। अंकटाड (यूएनसीटीएडी) सृजनात्मक उद्योग को एक ऐसी विकासशील अवधारणा के तौर पर परिभाषित करता है जो मनुष्य की रचनात्मकता, विचार, बौद्धिक संपदा, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के परस्पर संवाद के आधार पर चलती है।

सृजनात्मक अर्थव्यवस्था का आकार निर्धारण

सृजनात्मक अर्थव्यवस्था की विविधता इसके सही आकार के आकलन में चुनौती है। 2015 में यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई थी। `कल्चरल टाइम्स: द फर्स्ट ग्लोबल मैप ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज'। इसमें 2013 की सृजनात्मक अर्थव्यवस्था के आकार को मापने का प्रयास किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार, सांस्कृतिक और सृजनात्मक उद्योगों (सीसीआई) का वैश्विक आकार 2250 बिलियन यूएस डॉलर था, जो मोटे तौर पर 2013 के वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3% था और इस उद्योग में लगभग 29.5 मिलियन लोगों को रोजगार मिला था।

टीवी क्षेत्र ने राजस्व में सबसे अधिक 20% का योगदान दिया, जबकि रोजगार में सर्वाधिक 21% हिस्सेदारी दृश्य कला (विज़ुअल आर्ट्स) की रही । क्षेत्रीय संदर्भ में, 2013 में एशिया-प्रशांत (एपीएसी) क्षेत्र 743 बिलियन यूएस डॉलर के राजस्व के साथ सबसे बड़ा सीसीआई बाजार था, जो इसके क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 3% था। इसके बाद 709 बिलियन यूएस डॉलर के राजस्व के साथ यूरोप दूसरा सबसे बड़ा बाजार रहा था।

भारत की बात करें तो सांस्कृतिक और सृजनात्मक उद्योगों के अंतर्गत फिल्म उद्योग एक प्रमुख क्षेत्र है। अमेरिका के बाहर, राजस्व के आधार पर वैश्विक बॉक्स ऑफिस बाजारों में भारत छठे स्थान पर है। भारतीय बॉक्स ऑफिस के इस उल्लेखनीय आकार का कारण है भारत की भाषाई विविधता, जिनमें फिल्में बनाई जाती हैं।

सृजनात्मक अर्थव्यवस्था में व्यापार

सृजनात्मक वस्तुएं

यदि सृजनात्मक वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाए तो इसमें सात प्रमुख उद्योग आते हैं। इनमें कला-शिल्प, ऑडियो-विज़ुअल, डिजाइन, न्यू मीडिया, प्रदर्शन कला (परफॉर्मिंग आर्ट्स), प्रकाशन और विज़ुअल आर्ट्स शामिल हैं। सृजनात्मक वस्तुओं के वैश्विक निर्यातों में 2010 से 2019 के दौरान 5.5% की एएजीआर दर्ज

की गई। हालांकि इसी अवधि के दौरान भारत की सृजनात्मक वस्तुओं का निर्यात 7.2% की दर से बढ़ा। भारत का सृजनात्मक वस्तुओं का आयात, निर्यातों की तुलना में तेजी से बढ़ा और इसी अवधि में इसमें 9% की एएजीआर दर्ज की गई। भारत से सृजनात्मक वस्तुओं का निर्यात 2010 के 13.8 बिलियन यूएस डॉलर से 1.5 गुना वृद्धि के साथ 2019 में 21.1 बिलियन यूएस डॉलर हो गया।

भारत में, 2019 में सृजनात्मक वस्तुओं के कुल निर्यातों में 87.5% हिस्सा तो डिज़ाइन क्षेत्र से ही रहा। कला और शिल्प क्षेत्र का योगदान लगभग 9% का रहा। आयात के मामले में भी, 2019 में 41.4% के साथ डिज़ाइन क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी रही, जो 2010 की इसकी हिस्सेदारी से लगभग 14% ज्यादा रही। डिज़ाइन क्षेत्र के बाद 19.1% के साथ ऑडियो-विजुअल और 18.9% के साथ प्रकाशन क्षेत्र की हिस्सेदारी रही।

सृजनात्मक सेवाएं

भारतीय संदर्भ में, अंकटाड ने कुछ सेवाओं को सूचीबद्ध किया है, जिनके मूल्यांकन से सृजनात्मक सेवाओं के व्यापार को मापा जा सकता है। ये सेवाएं `अन्य के साथ-साथ बौद्धिक संपदा के उपयोग के लिए शुल्क'; `अनुसंधान और विकास'; `ऑडियो-विजुअल और संबंधित सेवाएं'; `कंप्यूटर सेवाएं'; और `सूचना सेवाएं' हैं।

वित्तीय वर्ष 2020 में भारत से सृजनात्मक सेवाओं के निर्यात ने 100 बिलियन यूएस डॉलर के आंकड़े को छू लिया और भारत के कुल सेवा निर्यात में सृजनात्मक सेवाओं के निर्यात का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2020 में लगभग 47% दर्ज किया गया, जो वित्तीय वर्ष 2011 में 43.5% था। वहीं दूसरी ओर, वित्तीय वर्ष 2020 में आयात 17.7 बिलियन यूएस डॉलर दर्ज किया गया और वित्तीय वर्ष 2020 में कुल सेवाओं के आयात में सृजनात्मक सेवाओं के आयातों की हिस्सेदारी 13.8% रही।

सृजनात्मक उद्योग में उभरती प्रौद्योगिकी

सृजनात्मक उद्योगों के संचालन में पिछले कुछ दशकों में लगातार प्रौद्योगिक उन्नयन देखा गया है। दुनिया ने पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट, सीडी, डीवीडी, डिजिटल भुगतान, स्ट्रीमिंग सेवाएं और सबसे ताजा बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्रा का आगमन देखा है। उनमें से कुछ को सटीक विकल्प नहीं मिला और सीडी और डीवीडी जैसे कुछ को गिरावट देखनी पड़ी।

एआई और मशीन लर्निंग

आईबीएम कॉर्पोरेशन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को मनुष्य जैसी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने वाले कंप्यूटर, रोबोट या किसी अन्य मशीन के रूप में परिभाषित किया है। इन दिनों में एआई की तमाम वाणिज्यिक संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। 2015 में एआई का बाजार मूल्य 7.2 बिलियन यूएस डॉलर दर्ज किया गया था। 2019 तक यह लगभग छह गुना बढ़ गया और इस अवधि के दौरान 60.2% की एएजीआर के साथ इसका बाजार मूल्य 42.8 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। उत्तरी अमेरिका लगभग 51% हिस्सेदारी के साथ इस क्षेत्र में अग्रणी रहा और 28% हिस्सेदारी के साथ एपेक दूसरे स्थान पर रहा।

सृजनात्मक उद्योगों में एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। 2016 में आई `सनस्प्रिंग' नाम की शॉर्ट फिल्म इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। क्योंकि इसे लिखा था बेंजामिन नाम के एआई बोट ने और यह संभव हुआ था न्यूरल नेटवर्क के उपयोग से। एक और उदाहरण फोर्ब्स का है, जिसके पास उत्तरी अमेरिका में अपने संपादकीय कर्मचारियों और वरिष्ठ स्तंभकारों के लिए `बर्टी' नाम का एक उपकरण है।

एक्सटेंडेड रिएलिटी (एक्सआर)

एक्सटेंडेड रिएलिटी वर्ष 2019 में एक्सआर का बाजार मूल्य 17.8 बिलियन यूएस डॉलर रहा और वर्ष 2025 तक इसके 296 बिलियन यूएस डॉलर के आंकड़े को छू लेने और 2019 से 2025 के दौरान 62% की सीएजीआर दर्ज किए जाने की उम्मीद है। सृजनात्मक उद्योगों में, विशेष रूप से मीडिया और मनोरंजन उद्योग एक्सआर के संदर्भ में सबसे बड़े अंतिम उपयोगकर्ताओं में से एक है।

एक्सआर क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल है। पिछले कुछ वर्षों से लोगों का स्क्रीन पर बीतने वाला समय बढ़ रहा है। इंटरनेट पर प्रति व्यक्ति बिताया जाने वाला प्रतिदिन का समय 2011 के 32 मिनट से बढ़कर 2020 में मोबाइल इंटरनेट पर 143 मिनट हो गया है।

ब्लॉकचेन

ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि, इसका उपयोग डिजिटल मुद्रा की अवधारणा से भी आगे है और इसमें सृजनात्मक उद्योगों के संचालन को पूरी तरह से बदल देने की क्षमता है। अगर संगीत और डिजिटल अधिकारों की बात करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्लॉकचेन में एकीकृत किया जा सकता है और यह पारंपरिक कॉन्ट्रैक्टों की जगह ले सकता है। अगर गीतकार, संगीतकार, गायकों जैसे स्टेकहोल्डरों को राजस्व का सही हिस्सा देने की बात करें तो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के जरिए स्टेकहोल्डरों के बीच ठीक और अधिक समावेशी तरीके से वितरण संभव हो सकता है।

चुनिंदा देशों में नीतियां

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया सृजनात्मक उद्योगों के लिए औपचारिक नीति तैयार करने वाले दुनिया के पहले देशों में से एक रहा है। ऑस्ट्रेलिया की पहली राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति 1994 में `क्रिएटिव नेशन' शीर्षक से जारी की गई थी। ऑस्ट्रेलिया में स्वदेशी के साथ-साथ प्रवासी संस्कृतियों के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 1997 में प्रदर्शन कला (परफॉर्मिंग आर्ट्स) के लिए आदिवासी केंद्र की स्थापना की। 1994 की नीति के बाद 2013 में `क्रिएटिव ऑस्ट्रेलिया' नामक दस्तावेज जारी किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति है।

यूके

यूके में 1997 में संस्कृति, मीडिया और खेल विभाग (डीसीएमएस) की स्थापना की गई। इसके बाद, एक सृजनात्मक उद्योग कार्यबल बनाया गया,

जिसने 1998 में सृजनात्मक मैपिंग दस्तावेज और 2001 में एक फॉलो-अप रिपोर्ट जारी की। 1998 के दस्तावेज में सृजनात्मक उद्योगों को परिभाषित करने और उसके आकार निर्धारण का प्रयास किया गया। इसके अलावा, 2018 में यूके सरकार और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज काउंसिल (सीआईसी) में सृजनात्मक संगठनों द्वारा निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए तीन साल के एक समझौते पर सहमति बनी।

दक्षिण कोरिया

1990 और 2000 के दशक में, दक्षिण कोरिया ने सृजनात्मक उद्योगों से संबंधित कई एजेंसियों की स्थापना की, जैसे कोरिया एसोसिएशन ऑफ हाई-टेक गेम इंडस्ट्री, कोरियन फेडरेशन ऑफ डिज़ाइन एसोसिएशन आदि। इसके अलावा, कोरिया क्रिएटिव कंटेंट एजेंसी (केओसीसीए) की स्थापना 2009 में पांच संबंधित संगठनों को एकीकृत करके की गई थी। 2013 में दक्षिण कोरिया ने `क्रिएटिव इकोनॉमी एक्शन प्लान एंड मेजर्स टू इस्टैब्लिश ए क्रिएटिव इकोनॉमिक इकोसिस्टम' नाम से एक महत्त्वपूर्ण ब्लूप्रिंट प्रकाशित किया।

थाईलैंड

2005 में, थाईलैंड क्रिएटिव एंड डिज़ाइन सेंटर (टीसीडीसी) ने ज्ञान प्रबंधन और विकास कार्यालय की देखरेख में अपना संचालन शुरू किया। 2018 में एक सरकारी संगठन, `क्रिएटिव इकनॉमी एजेंसी' (सीईए) का गठन किया गया, जो आर्थिक और सामाजिक वृद्धि के लिए सृजनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का काम करती है। थाईलैंड ने 2009 में क्रिएटिव थाईलैंड नीति भी शुरू की, जिसका उद्देश्य थाईलैंड को आसियान देशों में एक सृजनात्मक उद्योग केंद्र के रूप में विकसित करना था।

इंडोनेशिया

2007 में, इंडोनेशिया का पहला सांस्कृतिक उत्पाद सप्ताह शुरू किया गया। 2009 में इसका नाम बदलकर इंडोनेशियाई सृजनात्मक उत्पाद सप्ताह कर दिया गया। 2011 में, इंडोनेशिया ने एक नया मंत्रालय बनाया, जिसे पर्यटन और सृजनात्मक अर्थव्यवस्था मंत्रालय कहा जाता है। 2015 में, इंडोनेशिया सरकार ने सृजनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए इंडोनेशियाई एजेंसी (बीईकेआरएएफ) की स्थापना की। 2017 में, बीईकेआरएएफ ने फैशन, शिल्प, एप्लिकेशन, गेम डेवलपरों और रसोई संबंधी सहायक क्षेत्रों के लिए निवेश तैयारी स्तर (आईआरएल) की रूपरेखा जारी की।

भारत के सृजनात्मक उद्योग के लिए विकास रणनीतियों का चयन

भारत में सृजनात्मक उद्योगों की परिभाषा और खाका

भारत के लिए, पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य देश में सृजनात्मक उद्योग की बैंडविड्थ को परिभाषित करना होगा। अंकटाड ने इसकी एक परिभाषा दी है, किन्तु भारत अपने परिवेश और मूल्य आदि को ध्यान में रखते हुए सृजनात्मक उद्योगों को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है, जैसे थाईलैंड ने सृजनात्मक उद्योग की अपनी परिभाषा में थाई खाने और थाई पारंपरिक दवाओं को शामिल किया है।

वित्त

दुनिया भर के सांस्कृतिक और सृजनात्मक उद्योगों के सामने वित्तपोषण सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। इस उद्योग को बढ़ाने में मदद करने के लिए दुनिया के विभिन्न संस्थानों ने निधियों की स्थापना की है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय आयोग (ईसी) के पास सांस्कृतिक और सृजनात्मक क्षेत्र गारंटी फंड (सीसीएस जीएफ) है। भारत भी सृजनात्मक उद्योगों के लिए ऐसी ही विशेष गारंटी निधि स्थापित कर सकता है।

संयुक्त कार्यक्रमों की स्थापना

भारत विभिन्न बहुपक्षीय मंचों के साथ अपने संबंधों का उपयोग कर सृजनात्मक क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम भी स्थापित कर सकता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक, विरासत और भाषाई विविधता का संरक्षण और विकास करना तथा इसे बढ़ावा देना और सांस्कृतिक एवं सृजनात्मक क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता और आर्थिक क्षमता को बढ़ाना हो सकता है।

कॉपीराइट के मुद्दे का समाधान

कॉपीराइट, भारत में सृजनात्मक उद्योग की विभिन्न चुनौतियों में से एक है, जो अब भी प्रमुखता से बनी हुई है। ऐसा अनुमान है कि भारतीय फिल्मों को पायरेसी के कारण हर साल 2.7 बिलियन यूएस डॉलर के राजस्व का नुकसान होता है। भारतीय संगीत उद्योग में, पायरेसी की दर लगभग 67% है जो 27% के वैश्विक औसत से बहुत ज्यादा है। भारत अल्पावधि के लिए `स्वॉर्ड नेट एक्शन' के तहत चीनी मॉडल की मदद ले सकता है, जबकि दीर्घ काल में इसका समाधान सख्त कानूनों को लागू करना होना चाहिए।

सृजनात्मक जिलों/केंद्रों की स्थापना

भारत में 700 से अधिक जिले हैं। बड़े क्षेत्रफल में फैले इन जिलों की अपनी पहचान और संस्कृति है। केंद्र और राज्यों की सभी सरकारें, थाईलैंड के मॉडल पर कुछ ऐसे जिलों की पहचान कर सकती हैं, जिन्हें सृजनात्मक जिलों की श्रेणी में रखा जा सकता है। भारत में किसी सरकारी एजेंसी या ब्रिटिश काउंसिल जैसी विशेषज्ञ एजेंसियों के सहयोग से सृजनात्मक जिलों को चिह्नित करने के लिए गहन शोध किए जा सकते हैं।

सृजनात्मक उद्योगों के लिए एक विशेषज्ञ संस्थान का गठन

भारत में सृजनात्मक उद्योगों की मैपिंग के बाद, सृजनात्मक उद्योगों के विकास के लिए एक अलग नोडल एजेंसी का गठन करके ही इस उद्योग को पूरी गति दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि यूके (क्रिएटिव इंडस्ट्रीज काउंसिल) थाईलैंड (क्रिएटिव इकोनॉमी एजेंसी), इंडोनेशिया (एजेंसी फॉर द क्रिएटिव इकोनॉमी-बीईकेआरएफ) जैसे देशों में पहले से ही सृजनात्मक उद्योग विकास संस्थान मौजूद हैं। इन संस्थानों की तर्ज पर, भारत एक समर्पित सृजनात्मक उद्योग विकास संस्थान, भारतीय सृजनात्मक उद्योग एजेंसी (सीईए) भी स्थापित कर सकता है। ■

एक लचीले अफ्रीका का निर्माण: भारत की बढ़ी हुई भूमिका

अफ्रीका एक गतिशील महाद्वीप है, जिसमें वाणिज्य और विकास के असीमित अवसर हैं। बीते कुछ साल, भारत और अफ्रीका के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सहयोग में जबरदस्त बढ़ोत्तरी और गहनता के गवाह रहे हैं।

वस्तु निर्यात और निवेश

भारत और अफ्रीका के बीच तालमेल का अंदाजा भारत-अफ्रीका व्यापार संबंधों में मजबूत रुझानों से लगाया जा सकता है। 2021 में अफ्रीका के साथ भारत का कुल व्यापार 82.5 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जो दोनों के बीच अब तक का उच्चतम स्तर है। 2021 में अफ्रीका को भारत का निर्यात 37.9 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जो महामारी से पहले के स्तर से लगभग 28% अधिक रहा। भारत का आयात 2021 में 44.6 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जो 2020 की तुलना में लगभग 62% अधिक है। 2021 में अफ्रीका को भारत का निर्यात भारत के कुल निर्यात का 9.6% रहा, जबकि भारत के कुल आयात में अफ्रीका से भारत के आयात का हिस्सा 7.8% रहा। 2021 में इस महाद्वीप के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 6.8 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया।

भारत के साथ अफ्रीका का व्यापार

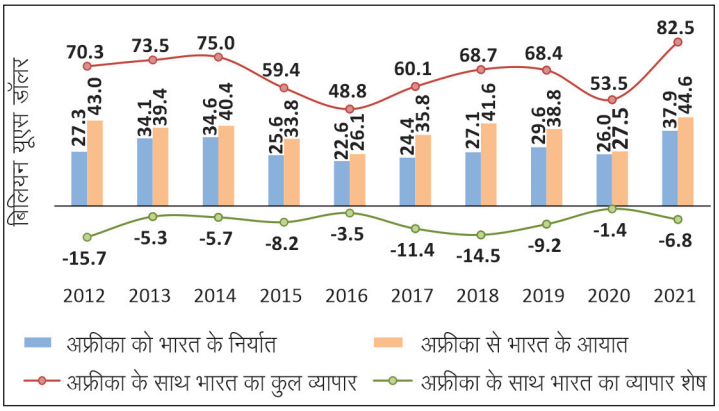

स्रोतः आईटीसी जेनेवा, कॉमट्रेड स्टैटिक्स पर आधारित; और इंडिया एक्ज़िम बैंक अनुसंधान

2021 में, दक्षिण अफ्रीका 15.8% हिस्सेदारी के साथ, अफ्रीका भारत के निर्यात के लिए अग्रणी देश रहा। अन्य प्रमुख निर्यात वाले देशों में नाइजीरिया (11.9%), मिस्र (8.7%), टोगो (7.7%) और केन्या (6.6%) शामिल हैं। जहां तक अफ्रीका से भारत के आयात का संबंध है, 2021 में भारत का प्रमुख आयात स्रोत दक्षिण अफ्रीका रहा। इस साल अफ्रीका से होने वाले कुल आयात में दक्षिण अफ्रीका की हिस्सेदारी 24.8% रही। 2021 में 20.5% की हिस्सेदारी के साथ नाइजीरिया दूसरा सबसे बड़ा आयात वाला देश रहा, इसके बाद गिनी (7.7%), मिस्र (6.7%) और अंगोला (4.4%) का स्थान रहा।

भारत से अफ्रीका को निर्यात होने वाली वस्तुओं में सबसे प्रमुख पेट्रोलियम उत्पाद (मुख्य रूप से परिष्कृत) रहे, जिनका 2021 के दौरान भारत से अफ्रीका को कुल निर्यात में 19.1% योगदान रहा। इसके बाद वाहन (10.4%), फार्मासूटिकल्स (10.3%) और अनाज (8.5%) रहे। 2021 के दौरान अफ्रीका से भारत के कुल आयात में खनिज ईंधन (मुख्य रूप से कच्चा तेल) का 47.8% हिस्सा रहा, इसके बाद मोती, कीमती पत्थर और धातु (25.4%) और तांबे की वस्तुएं (4%) रहीं।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 1996 से मार्च 2022 के दौरान अफ्रीका में भारत के 73.9 बिलियन यूएस डॉलर के संचयी निवेश को मंजूरी दी गई। मॉरीशस, मोज़ाम्बिक, सूडान, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका में भारत के निवेश वाले शीर्ष देश रहे। अफ्रीका के विनिर्माण क्षेत्र (36%) में अप्रैल 2010-मार्च 2022 के दौरान सबसे अधिक भारतीय निवेश हुआ। भारतीय निवेश को आकर्षित करने वाले अन्य प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय, बीमा, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएं (22%), कृषि और संबद्ध क्षेत्र (14%), परिवहन, भंडारण और संचार सेवाएं (11%) शामिल रहे।

अफ्रीका में परियोजना निर्यात

एक देश से परियोजना निर्यात इसकी तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को दिखाता है और लंबी अवधि में विदेशी मुद्रा के स्रोत के तौर पर काम करता है। 2016-2021 के दौरान, भारत ने अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) द्वारा 831.7 मिलियन यूएस डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट से हासिल किए। 2016-2021 के दैरान भारतीय कंपनियों के द्वारा प्राप्त किए गए कॉन्ट्रैक्टों में एएफडीबी द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त बहु-राष्ट्रीय परियोजनाओं का प्रमुख हिस्सा रहा। भारतीय कंपनियों को मिले कुल कॉन्ट्रैक्टों में ऐसी परियोजनाओं की हिस्सेदारी 41% रही। बहु-राष्ट्रीय परियोजनाओं के बाद, एएफडीबी द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों को प्राप्त कॉन्ट्रैक्टों में तंज़ानिया की 16% हिस्सेदारी रही। इसके बाद मोरक्को (14%), इथियोपिया (7%), युगांडा (5%) और केन्या (4%) का स्थान रहा। एएफडीबी वित्तपोषित परियोजनाओं में मूल्य के आधार पर भारतीय कंपनियों को मिले कॉन्ट्रैक्टों में विद्युत क्षेत्र की प्रमुख हिस्सेदारी रही। 2016-2021 के दौरान भारतीय कंपनियों को मिले कॉन्ट्रैक्टों की कुल कीमत में 82% हिस्सेदारी इसी क्षेत्र की रही। इसके बाद परिवहन (13%), कृषि (3%),पानी और स्वच्छता (1%) क्षेत्र की हिस्सेदारी रही।

2016 से 2021 के दौरान, अफ्रीका में विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं में भारतीय परियोजना निर्यातकों ने कुल 1.3 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य के 285 कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। अफ्रीका में मूल्य के आधार पर, भारतीय कंपनियों द्वारा हासिल किए गए कॉन्ट्रैक्टों का प्रमुख प्राप्तकर्ता मिस्र 16% हिस्सेदारी के साथ रहा। इसके बाद इथियोपिया (15%), नाइजीरिया (10%) और दक्षिण अफ्रीका (7%) का स्थान रहा। क्षेत्रों के आधार पर, 2016-2021 के दौरान भारत ने विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अफ्रीकी कॉन्ट्रैक्टों का सबसे बड़ा हिस्सा ऊर्जा और निष्कर्षण क्षेत्र (56%)

में हासिल किया। इसके बाद परिवहन (12%), उद्योग, व्यापार और सेवा (9%) और आईसीटी (7%) क्षेत्र का स्थान रहा।

सुदृढ़ अफ्रीका के निर्माण में भारत की भूमिका को बढ़ाने वाली रणनीतियां

अफ्रीकी देशों के साथ अपने व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत की रणनीति में एक एकीकृत दृष्टिकोण होगा, जिसमें अन्य के साथ-साथ, अफ्रीका को जीवीसी के साथ एकीकृत करना, अफ्रीका के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करना और अफ्रीका में व्यापार वित्त की सुविधा प्रदान करना शामिल है। कृषि व्यवसाय, परिधान और कपड़ा, फार्मासूटिकल्स और ऑटोमोटिव से संबंधित उपभोक्ता-संचालित सामान भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अवसर हैं, जहां अफ्रीका, एएफसीएफटीए के माध्यम से शुल्क संबंधी बाधाओं को समाप्त कर रहा है।

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण

प्रचुर मात्रा में भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद अपर्याप्त कृषि अवसंरचना और औसत उत्पादकता की बाधाएं भारत को इस क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में आवश्यक उपाय करने का मौका प्रदान करती हैं। यह काम ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों की आपूर्ति, ट्रैक्टर निर्माण या कृषि-आधारित उपकरणों में निवेश, सौर ऊर्जा संचालित पंपों, सिंचाई के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित सहायता के माध्यम से किया जा सकता है। इसके साथ मार्केटिंग और वित्त पर ध्यान केंद्रित करने वाले संयुक्त संस्थानों के निर्माण से इस क्षेत्र की वृद्धि में सहयोग किया जा सकता है।

स्वास्थ्य सेवा और फार्मासूटिकल वैल्यू चेन

अफ्रीका में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए दो वृहद रास्तों की मदद ली जा सकती हैं। पहला रास्ता है, भारत सरकार समर्थित ऋण-व्यवस्थाओं का, जो भारत के अफ्रीकी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करती है और दूसरा रास्ता पीपीपी मॉडल का है। यहां, प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का निर्माण ऋण-व्यवस्थाओं के तहत हो सकता है, जबकि तृतीयक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का निर्माण पीपीपी के जरिये किया जा सकता है। पीपीपी मॉडल के तहत अस्पताल चलाने में उल्लेखनीय अनुभव रखने वाले प्रमुख भारतीय अस्पताल संचालक अफ्रीका के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की जरूरतों के लिए आदर्श भागीदार हो सकते हैं। पीपीपी इस बारे में एक बेहतर समाधान साबित हो सकता है, इसमें निवेश संबंधी जोखिम का खतरा भी कम होता है, दक्षता में सुधार होता है और ज्यादा समावेशी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अस्पताल निर्माण और प्रशासन में भारत की दोहरी विशेषज्ञता अफ्रीका-भारत द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। अफ्रीका औषधीय और दवा उत्पादों में आयात पर निर्भर है। कई भारतीय कंपनियों ने अफ्रीका में बड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली रियायती दर की गुणवत्ता वाली दवाओं की आपूर्ति के लिए स्थानीय विनिर्माण इकाइयां या संयुक्त उपक्रम स्थापित किए हैं। बड़े पैमाने पर, क्षेत्रीय दवा या वैक्सीन निर्माण संयंत्र और संयुक्त अनुसंधान और शीत भंडारण सुविधाएं भी स्थापित की जा सकती हैं।

स्वच्छ ऊर्जा के लिए वित्तीय सहायता

भारत के नेतृत्व वाला अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) अफ्रीकी देशों को सौर ऊर्जा समाधान देने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। फिलहाल, अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा प्रकाश, मोबाइल फोन चार्ज करने, कम क्षमता वाले बिजली उपकरण जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। हालांकि, अफ्रीकी देशों में स्थापित क्षमता, वास्तविक क्षमता के मुकाबले बहुत कम है। भारत सरकार ने भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीका के लिए प्रतिबद्ध 10 बिलियन यूएस डॉलर की रियायती ऋण-व्यवस्थाओं में से 2 बिलियन यूएस डॉलर की रियायती ऋण-व्यवस्थाएं अफ्रीका में सौर परियोजनाओं के लिए निर्धारित की हैं। हालांकि, ऋण-व्यवस्थाओं के तहत आने वाली इन सौर परियोजनाओं का उन्नयन अपेक्षाकृत कम रहा है, जिसकी आंशिक वजह भारतीय सामग्री की जरूरत का कम होना है। भारत की आयात निर्भरता कम करने, लागत प्रतिस्पर्धा और घरेलू उत्पादन और सौर पैनलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना महत्त्वपूर्ण है। इससे सौर क्षेत्र में अफ्रीका के भारत के परियोजना निर्यात को बढ़ाने के साथ ही अफ्रीका के स्वच्छ बिजली उत्पादन में भी मदद मिलेगी।

बुनियादी ढांचागत वित्तपोषण के लिए वैकल्पिक समाधान

परियोजना निर्यातों के वित्तपोषण के लिए स्थानीय मुद्रा में वित्तपोषण या काउंटर ट्रेड जैसे वैकल्पिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। ये उपाय खासतौर पर संसाधन संपन्न देशों के मामले में भविष्य में चुकौती और कम आय वाले देशों को उनके विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने वाले हो सकते हैं। भारत और अफ्रीका संयुक्त रूप से कौशल और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और तकनीकी सहायता जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ मिलकर त्रिपक्षीय सहयोग की संभावनाओं को भी तलाश सकते हैं। अफ्रीका की बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निवेश करने के लिए त्रिपक्षीय साझेदारी की पहल को संबंधित देशों के विकास वित्त संस्थानों को शामिल करने वाले एक अलग कोष की स्थापना या समौझतों के जरिये और गति दी जा सकती है।

व्यापार वित्त की उपलब्धता बढ़ाना

एएफडीबी और अफ्रेक्ज़िम बैंक के अनुमानों के अनुसार, अफ्रीका में व्यापार वित्त की अधूरी मांग का मूल्य 2019 में 81.8 यूएस बिलियन डॉलर और पिछले एक दशक में औसतन 91 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर रहा। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि वैश्विक स्तर के 80% की तुलना में अफ्रीका के केवल 40% व्यापार में बैंकों की मध्यस्थता है। जैसा कि एएफडीबी अनुसंधान[1] में पाया गया है, 2011 से 2019 के दौरान, अफ्रीका के प्रमुख संपर्क बैंकों ने अपने व्यापार वित्त पुष्टि गतिविधियों में महत्त्वपूर्ण गिरावट देखी। नियामक प्रतिबंध और उच्च अनुपालन लागत अफ्रीका में अंतरराष्ट्रीय कंफर्मिंग बैंकों के पीछे हटने की प्रमुख वजहें रही हैं, जिस वजह से खासकर एसएमई के लिए व्यापार वित्त उपलब्धता कम हो गई हैं। इस अंतर को भरने के लिए, विकास वित्त संस्थान अफ्रीका में गैर-पारंपरिक कंफर्मिंग बैंकों का सहयोग करने के लिए जोखिम भागीदारी और ट्रांज़ैक्शन गारंटी समझौते जैसे वित्तीय उपकरण विकसित कर सकते हैं। ■

[1] अफ्रीका में बैंकों की पुष्टि और व्यापार वित्त, अफ्रीका अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त विवरण : एएफडीबी 2022

भारतीय अर्थव्यवस्था पर रूस–यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव

यूक्रेन में रूस के विशेष अभियान, अमेरिका और उसके सहयोगियों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ के देशों द्वारा रूस पर लगाए गए दंडात्मक प्रतिबंधों का प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। हालांकि, प्रत्यक्ष व्यापार में रूस और यूक्रेन की कम हिस्सेदारी के चलते भारत के समग्र व्यापार प्रवाह पर रूस-यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव कम होने की उम्मीद है। जबकि 2021-22 में भारत के वस्तु व्यापार में रूस की हिस्सेदारी 1.3% रही (निर्यात - 0.8%; आयात - 1.6%), 2021-22 में भारत के कुल व्यापार में यूक्रेन का हिस्सा 0.3% (निर्यात - 0.1%; आयात - 0.5%) रहा)।

इनपुट लागत में बढ़त और मैक्रोइकनॉमिक वैरिएबल

संभावित वस्तु मूल्य वृद्धि से इनपुट लागत में भारी वृद्धि हो सकती है, जिससे निर्यात उत्पादों और घरेलू खपत की वस्तुओं में वृद्धि हो सकती है। लंबे समय तक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का गंभीर प्रभाव भारत के मैक्रोइकनॉमिक वैरिएबल पर हो सकता है। यह जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, बचत, रुपये की विनिमय दर, ब्याज दर, व्यापार, चालू खाते और अंत में भारत के राजकोषीय घाटे को प्रभावित कर सकता है।

विनिमय दर: तेल की ऊंची कीमतों और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता के कारण रुपये पर दबाव काफी बढ़ गया है। तेल की ऊंची कीमतों के नतीजे में व्यापार घाटा बढ़ेगा और रुपये की कीमत में भी गिरावट होगी। रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरु होने के बाद मई के अंत तक रुपये की कीमत में 4.3% की गिरावट आई है। बढ़ते आयात बिल के कारण व्यापार घाटे के बढ़ने और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा लगातार बिक्री के कारण भारतीय रुपये पर गंभीर दबाव पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में, आरबीआई ने देश में विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ाने, भारतीय बाजार में नई विदेशी पूंजी को आकर्षित करने और रुपये की कीमत पर नियंत्रण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता प्रबंधन के लिए मार्च और अप्रैल 2022 में 5 बिलियन यूएस डॉलर/ आईएनआर क्रय/ विक्रय स्वॉप किया है। इसके अलावा, मौद्रिक नीति संबंधी उपाय भी किए गए, जिनमें नीतिगत दरों को बढ़ाना भी शामिल है। युद्ध संबंधी अनिश्चितताओं, जोखिम से बचने की प्रवृत्तियों, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और फेडरल रिजर्व द्वारा नीति को सख्त करने के कारण विनिमय दर अस्थिर रहने की संभावना है।

मुद्रास्फीति: वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और बढ़ी हुई अनिश्चितताओं से कच्चे तेल के उत्पादों की घरेलू कीमतें बढ़ेंगी और घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। रूस-यूक्रेन संघर्ष के चलते कच्चे तेल की कीमतों में लगातार आ रही तेजी और बढ़ गई है। इसके अलावा, अन्य भू-राजनीतिक चिंताएं और भारतीय रुपये पर इसका प्रभाव आने वाली तिमाहियों में भारतीय मुद्रास्फीति वक्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कच्चे तेल का यह प्रभाव उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर दो चैनलों से आता है। पहला, प्रत्यक्ष चैनल वह है, जहां कच्चे तेल के उत्पाद स्वयं सीपीआई में घटक के रूप में होते हैं। छोटी अवधि में, कच्चे तेल उत्पादों की कीमतों में बदलाव सूचकांक में उनके भारित योगदान के कारण सीधे सीपीआई को प्रभावित करेगा। दूसरा, कच्चे तेल का उपयोग करके बनी अन्य वस्तुओं की खुदरा कीमतों में भी समय के साथ वृद्धि होगी। इसका सीपीआई पर प्रभाव होगा जो कि अप्रत्यक्ष प्रभाव है। इस प्रकार, मुद्रास्फीति पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का शुद्ध प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों के योग से निकलता है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का डब्ल्यूपीआई और सीपीआई मुद्रास्फीति पर प्रभाव ईंधन की घरेलू खुदरा कीमतों के आधार पर तय होगा। इंडिया रेटिंग्स की आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, अगर मुद्रा में गिरावट की गणना न की जाए तो पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में 10% की वृद्धि से खुदरा मुद्रास्फीति में 42 बीपीएस और थोक मुद्रास्फीति में 104 बीपीएस की वृद्धि होगी। इसी तरह, मुद्रा में गिरावट की गणना को छोड़ दिया जाए तो सूरजमुखी तेल की कीमत में 10% की वृद्धि से सीपीआई में 12.6 बीपीएस और थोक मुद्रास्फीति में 2.48 बीपीएस की वृद्धि होगी। अकेले इन दो वस्तुओं की कीमतों में 10% की वृद्धि खुदरा और थोक मुद्रास्फीति को क्रमशः 55 बीपीएस और 109 बीपीएस तक बढ़ा सकती है, जो उपभोक्ता व्यवहार और क्रय शक्ति को प्रभावित करती है।

वित्तीय सेवाएं : अनिश्चितताओं के कारण सुरक्षित निवेश की चाह के कारण उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी बाहर की ओर गई है और इनमें भारत भी शामिल है। रूस-यूक्रेन संघर्ष और इस कारण लगे प्रतिबंधों, उच्च मुद्रास्फीति और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में संभावित वृद्धि के कारण आने वाले महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह अस्थिर रहने की उम्मीद है। बाजार से एफपीआई की लगातार निकासी और घरेलू इक्विटी में भारी बिकवाली से इक्विटी बाजार और भारत के बाजार मूल्यांकन पर असर पड़ सकता है। ऐसी भारतीय कंपनियां जिनका एक्सपोज़र रूस, यूक्रेन में है और अन्य यूरोपीय कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति के तनावपूर्ण होने की भी आशंका है।

सार्वजनिक सेवाएं: तेल की ऊंची कीमतों का असर भारत के बजट खर्चों पर पड़ेगा, जिससे राजकोषीय लक्ष्य गड़बड़ा जाएंगे। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के सरकारी वित्त पर प्रभाव के कारण भारत सरकार पूंजीगत खर्चों में कटौती कर सकती है। मौजूदा समय में प्रक्रिया में चल रहे रक्षा उपकरणों के आयात पर भी असर पड़ सकता है।

ट्रेड चैनल और चालू खाते पर प्रभाव

निर्यात के मोर्चे पर, फार्मासूटिकल उत्पाद आवश्यक वस्तु होने के कारण फिलहाल प्रतिबंधों से बाहर हैं। भारत का फार्मासूटिकल निर्यात, भारत से रूस-यूक्रेन दोनों को होने वाला सबसे बड़ा निर्यात है, लेकिन प्रतिबंधों से बाहर होने के कारण इस पर मामूली प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। रूस और यूक्रेन दोनों ही भारतीय चाय के प्रमुख आयातक हैं। इस संकट से घरेलू बाजार में चाय की अधिक आपूर्ति होने की संभावना है, जिससे चाय की कीमतों में गिरावट आ सकती है। इसके साथ, रुपये में गिरावट से निर्यात के प्रतिस्पर्धी होने से भारत के निर्यात वाले क्षेत्रों को लाभ होने की उम्मीद है। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, निर्यात बीमा शुल्क में वृद्धि और शिपिंग भाड़े के कारण भी भारतीय निर्यातकों की व्यापारिक लागत बढ़ने की उम्मीद है। अगर आयात की बात करें तो कच्चे तेल, उर्वरक, धातु और खाद्य तेल की ऊंची कीमतों के कारण भारत के आयात मूल्य बढ़ेंगे। भारत का बाह्य क्षेत्र वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण अस्थिर बना हुआ है और निकट भविष्य में भी उसके ऐसा ही बना रहने की उम्मीद है।

दूसरी ओर, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि स्टील और एल्युमीनियम जैसे क्षेत्रों के मामले में अच्छी साबित हो सकती है, जिससे घरेलू प्राथमिक इस्पात निर्माताओं और एल्युमीनियम स्मेल्टर्स को ज्यादा लाभ हो सकता है। हालांकि, निर्माण, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो इन उत्पादों के अंतिम उपयोगकर्ता हैं।

यूक्रेन और रूस में 75% नियॉन गैस (केवल यूक्रेन में ही 70%) का उत्पादन किया जाता है, जिसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में होता है। इससे सेमीकंडक्टर्स की कमी से जूझ रहे ऑटोमोबाइल सेक्टर के और प्रभावित होने की आशंका है। रूसी प्रतिबंधों से सेमीकंडक्टर उत्पादन में और कमी आने की आशंका है। विश्व में पैलेडियम के सबसे बड़े उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं में से एक होने के कारण और रूसी प्रतिबंधों की वजह से पनपीं अनिश्चितताओं के कारण पैलेडियम की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इस प्रकार, खाद्य, ईंधन और उर्वरक की ऊंची कीमतों के कारण आयात बिलों में संभावित वृद्धि; प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की घरेलू मांग में कमी और पूंजी प्रवाह की अनिश्चितता, भारत के चालू खाता घाटे को और बढ़ा सकती है। इससे अल्पावधि में पूंजी भंडार प्रभावित हो सकते हैं।

रक्षा खर्च में बढ़ोत्तरी

भारत के वर्तमान सैन्य शस्त्रागार में रूस निर्मित या रूसी-डिज़ाइन वाले उपकरण बड़ी मात्रा में हैं, जिन्हें ज्यादातर दोनों देशों को बीच सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के जरिये खरीदा गया है। रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण, हथियारों के आयात के लिए रूस पर भारत की निर्भरता कम होने की उम्मीद है। हालांकि, इससे भारत को अपने आयात स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता होगी, जिससे देश के रक्षा खर्च में वृद्धि होगी। दूसरी ओर, `मेक इन इंडिया' के तहत रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के लगातार प्रयासों से रूसी रक्षा उत्पादों पर भारत की निर्भरता कम होगी। इससे बड़े रक्षा बजट का एक हिस्सा विकास और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा।

रूस में भारतीय बैंकों का एक्सपोज़र

कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी (एसबीआई और केनरा बैंक का संयुक्त उद्यम) को छोड़कर, भारतीय बैंकों की रूस में कोई सहायक कंपनी, शाखाएं या प्रतिनिधि कार्यालय नहीं हैं। भारतीय बैंकों के लिए यहां वित्त व्यवसाय अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि भारत और रूस के बीच व्यापार का आकार सीमित है। भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक का रूस में एक्सपोज़र 10 मिलियन यूएस डॉलर से कम है। हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, बिगड़ते भू-राजनीतिक हालातों और वैश्विक प्रतिबंधों के कारण भारतीय बैंकों ने रूसी संस्थाओं से जुड़े किसी भी लेनदेन को प्रक्रिया में नहीं लेने का फैसला किया है। भारतीय बैंक वर्तमान में रूसी व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों से निपटने के तरीके तलाश रहे हैं। इसलिए, भारतीय बैंकों पर मौजूदा संघर्ष के प्रभाव कम रहने की उम्मीद है।

उत्पादों के वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत

मौजूदा संकट का एक सकारात्मक संभावित लाभ यह है कि भारत कई उत्पादों के वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर सकता है, जिनकी आपूर्ति रूस द्वारा की जा रही थी और वर्तमान में उनकी आपूर्ति में बाधाएं आ रही हैं। उदाहरण के लिए, रूस इस्पात का एक प्रमुख निर्यातक है और भारत इस्पात उत्पादों के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रूप में उभर सकता है। यूरोपियन यूनियन के मामले में यह खासतौर पर हो सकता है।

2021 में यूक्रेन लौह अयस्क (एचएस 2601) का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक रहा, जबकि भारत विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा और रूस 9वां सबसे बड़ा निर्यातक रहा। इसलिए, यह संघर्ष भारतीय लौह अयस्क उत्पादकों को अपना निर्यात बढ़ाने का मौका भी देता है। भारतीय कृषि निर्यात के मामले में भी ऐसा ही है। भारत के लिए गेहूं, मक्का, बाजरा, प्रसंस्कृत खाद्य, मेवा, कन्फेक्शनरी, फल और फलों के रस, दालों और अनाज के निर्यात में अवसर हैं। इन वस्तुओं के भारतीय निर्यातकों को इनकी बढ़ी हुई वैश्विक मांगों का लाभ हो सकता है और वे वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों के रूप में उभर सकते हैं।

हरित ऊर्जा की ओर और अक्षय ऊर्जा में बढ़ता निवेश

कच्चे तेल के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के बढ़ते इस्तेमाल से भारत को आयातित ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। इसी प्रकार देश को तेल की कीमतों के झटकों से भी राहत मिल सकती है। भारत के लिए वर्तमान परिदृश्य शायद अक्षय ऊर्जा और वैकल्पिक ईंधन में अधिक निवेश और आने वाले वर्षों में अक्षय ऊर्जा की खपत को बढ़ाने के लिए आदर्श है। इससे देश में हरित ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त होगा। ■

एक संतुलित भारत–यूरोपीय संघ एफटीए की ओर

भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में 2021 में एक नई गतिशीलता देखने को मिली। दोनों अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने के लिए एक व्यापक करार पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्सुक रहीं। भारत और यूरोपीय संघ के लिए यह समय अपने सुगठित व्यापार और निवेश प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाते हुए इन संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार करार (एफटीए) के लिए वार्ता के दौरान निम्नलिखित कुछ पहलू विचारणीय हैं:

- ***उत्पादों की सकारात्मक सूची के बजाय नकारात्मक सूची पर ध्यान***

किसी भी शुल्क युक्तिकरण नीति के लिए क्षेत्र-विशेष प्रभाव का विश्लेषण महत्त्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्यापकीकरण से उत्पन्न गलत अनुमान से बचाता है। इस पड़ताल के आधार पर, उत्पादों की एक संवेदनशील/ नकारात्मक सूची बनाई जानी चाहिए। इसमें उन उत्पादों को शामिल किया जाए जो शुल्क उदारीकरण की स्थिति में घरेलू अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हों। एफटीए पर बातचीत के दौरान आयात शुल्क से छूट पाने वाले उत्पादों की सूची पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जो संवेदनशील / नकारात्मक सूची में हों और जिनकी शुल्क रियायतों को सीमित कर संबंधित क्षेत्र और उससे जुड़े लोगों के हितों की रक्षा की जानी है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्तमान एफटीए बातचीत के लिए, संवेदनशील क्षेत्रों में मादक पेय, ऑटोमोबाइल और डेयरी क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें ईयू भारतीय बाजार तक पहुंच बढ़ाने की मांग करेगा।

- ***यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षरित अन्य एफटीए के सापेक्ष व्यापार उदारीकरण***

एफटीए के तहत रियायतों के लिए बातचीत करते समय, भारत को यूरोपीय संघ के बाजार में भारत के प्रतिस्पर्धियों (जैसे वियतनाम, बांग्लादेश और श्रीलंका) के साथ अपने एफटीए के साथ-साथ जीएसपी ढांचे के तहत यूरोपीय संघ द्वारा की गई छूटों को ध्यान में रखना होगा। प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर उत्पाद को चिह्नित करने, उसके बाद देश-वार तुलनात्मक टैरिफ विश्लेषण से पता चलता है कि यदि भारत के प्रतिस्पर्धियों के अनुरूप शुल्क (टैरिफ) रियायतें प्रदान की जाती हैं तो निर्यात के विस्तार के लिए बहुत अधिक अवसर मौजूद हैं। विशेष रूप से, बुने हुए और गैर-बुने हुए दोनों तरह के परिधान उत्पादों (एचएस-61 और एचएस-62) और जूते व गाइटर (एचएस-64) तथा अन्य के मामले में अपार अवसर मौजूद हैं। भारत वर्तमान में एचएस-61 के तहत यूरोपीय संघ को 2.9 बिलियन यूएस डॉलर के उत्पादों का निर्यात करता है और 9.4% की दर से एएचएस चुकाता है, जो कि बांग्लादेश (0%) और वियतनाम (3.8%) जैसे इसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कहीं अधिक है। वैश्विक स्तर पर, यूरोपीय संघ ने 2021 में 93.4 बिलियन यूएस डॉलर की राशि के बुने हुए या क्रोशिए किए (एचएस-61) परिधान उत्पाद व कपड़ों के सामान का आयात किया। बांग्लादेश ईबीए योजना के तहत 0% पीआरएफ का लाभ उठाते हुए यूरोपीय संघ को एचएस-61 श्रेणी में 15 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य का निर्यात करता है जबकि यूरोपीय संघ के साथ अपने एफटीए के तहत वियतनाम 3.8% की दर से पीआरएफ अदा करता है और इस श्रेणी के तहत 2.3 बिलियन यूएस डॉलर के उत्पादों का निर्यात करता है। परिधान उत्पादों और कपड़े की वस्तुओं के मामले में, बिना बुने हुए या क्रोशिए किए हुए (एचएस-62) के यूरोपीय संघ को भारतीय निर्यात पर 9% की दर से एएचएस लगता है और भारत लगभग 2.6 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात करता है। यूरोपीय संघ ने 2021 में 85.4 बिलियन यूएस डॉलर की राशि के परिधान और कपड़ा उत्पादों का आयात किया जो बुने हुए या क्रोशिए किए हुए (एचएस-62) नहीं थे। बांग्लादेश ईबीए योजना के तहत 0% पीआरएफ का लाभ उठाते हुए यूरोपीय संघ को एचएस -62 श्रेणी के अंतर्गत 9.3 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य निर्यात करता है। वियतनाम अपनी मानक जीएसपी पात्रता और यूरोपीय संघ के साथ एफटीए के कारण 6.3% की दर से पीआरएफ चुकाते हुए इस श्रेणी के तहत 2.9 बिलियन यूएस डॉलर के उत्पादों का निर्यात करता है।

भारत, एचएस-64 के तहत सूचीबद्ध फुटवियर और गैटर के मामले में वर्तमान में 1.6 फीसदी की दर से एएचएस चुकाते हुए 1.4 बिलियन यूएस डॉलर के सामान का निर्यात करता है। यूरोपीय संघ ने 2021 में 59.6 बिलियन यूएस डॉलर के फुटवियर और गैटर (एचएस-64) का आयात किया। वियतनाम अपनी मानक जीएसपी पात्रता और यूरोपीय संघ के साथ एफटीए के कारण 2.1% के पीआरएफ का सामना करता है और इस श्रेणी के तहत 7.5 बिलियन यूएस डॉलर के उत्पादों का निर्यात करता है। उत्पाद श्रेणियों जैसे रेलवे या ट्रामवे (एचएस-87), एल्युमीनियम और उसके सामान (एचएस-76), कार्बनिक रसायन (एचएस-29), लोहे और स्टील की वस्तुएं (एचएस-73) के अलावा अन्य उत्पादों में भारत को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उच्च शुल्क दरों का सामना करना पड़ रहा है। संक्षेप में, यूरोपीय संघ में भारतीय निर्यात के विस्तार की संभावना भारत के सापेक्ष इन प्रतिस्पर्धी देशों को यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान की जाने वाली शुल्क रियायतों पर निर्भर करेंगी।

- ***गैर–शुल्क बाधाओं (एनटीएम) को कम करना***

यूरोपीय संघ को भारत के निर्यात के मामले में, शुल्क दरों में कमी से भारतीय निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि यूरोपीय संघ में आयात शुल्क पहले से ही कम है। भारत उच्च बाजार पहुंच के अवसरों का लाभ तभी उठा सकता है जब एनटीएम का सही से समाधान किया जाए। इंटीग्रेटेड ट्रेड इंटेलीजेंस पोर्टल (आई-टीआईपी) से दिसंबर, 2021 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ द्वारा भारत पर द्विपक्षीय रूप से लागू एनटीएम समेत ईयू के विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों (भारत सहित) पर 2618 एनटीएम

हैं। 2618 एनटीएम में से 510 को लागू किया गया है और 2108 को शुरू किया गया। अलग-अलग शब्दों में, सैनिट्री और फाइटोसैनिट्री (एसपीएस) और व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (टीबीटी) उपाय सबसे बड़े एनटीएम हैं और इनमें 944 एसपीएस (148 लागू और 796 शुरू किए गए), और 1,464 टीबीटी (153 लागू और 1311 शुरू किए गए) शामिल हैं।

विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों (भारत सहित) पर यूरोपीय संघ द्वारा लागू एनटीएम में से 38 उपाय द्विपक्षीय रूप से भारत पर लगाए गए हैं। ये डंपिग रोधी (एडीपी) उपायों (15), प्रतिकारी उपायों (4) और सैनिट्री और फाइटोसैनिट्री उपायों (19) के तौर पर लगाए गए। डब्ल्यूटीओ आई-टीआईपी के व्यापक क्षेत्र वर्गीकरण के अनुसार, एनटीएम के माध्यम से जीवित पशु और उत्पाद व सब्जी उत्पाद अधिकतम संरक्षित क्षेत्र हैं। इसके बाद तैयार खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, स्प्रिट, सिरका और तंबाकू, रासायनिक और संबद्ध उद्योगों के उत्पाद, मशीनरी और बिजली के उपकरण, अन्य शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर यूरोपीय संघ को डेयरी उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया जटिल है और इसके लिए कई कठोर आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है। ऐसा ही मामला यूरोपीय संघ से भारत को कृषि-खाद्य निर्यात का भी है, जो विभिन्न गैर-शुल्क बाधाओं का सामना करता है। इस तरह भारत और यूरोपीय संघ को इन गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है ताकि दोनों पक्षों को और आसानी से व्यापार करने में मदद मिल सके।

भारत और यूरोपीय संघ `म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट' (एमआरए) तैयार करने की दिशा में भी काम कर सकते हैं। एमएआर वे समझौते हैं जो व्यापार से जुड़ी तकनीकी बाधाओं को घटाने के लिए दो व्यापारिक साझेदारों के बीच किए जाते हैं। ये `अनुरूपता मूल्यांकन' को पारस्परिक मान्यता प्रदान करने वाले समझौते हैं। अनुरूपता मूल्यांकन (यानी, उत्पाद सुरक्षा और मानक परीक्षण) तकनीकी नियमों और मानकों के अनुसार निरीक्षण, परीक्षण, प्रमाणन और लाइसेंसिंग सहित विभिन्न रूपों में किया जा सकता है और इसका उद्देश्य सुरक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य जोखिमों को रोकना है। यूरोपीय संघ को यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि भारत में नामित परीक्षण निकाय यूरोपीय संघ की तकनीकी आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक परीक्षण कर सकता है और ठीक ऐसा ही भारत के लिए भी है। यह भारत में उत्पादित और प्रमाणित उत्पाद को यूरोपीय संघ में आगे परीक्षण किए बिना यूरोपीय संघ को निर्यात करने की अनुमति देगा और इसके विपरीत, यह निर्धारित करेगा कि उत्पाद यूरोपीय संघ की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं। इसके अतिरिक्त, भारत को प्रमाणन के लिए संस्थागत हस्तक्षेप की भी आवश्यकता है। इस संबंध में, यूरोपीय संघ की सहायता से ब्लॉकचैन पर आधारित आपूर्तिकर्ता सत्यापन और प्रमाणन के लिए डिजिटल ग्लोबल आइडेंटिटी सिस्टम विकसित किया जा सकता है, जो एसएमई के वर्चस्व वाले उद्योगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। ऐसे हस्तक्षेप दोनों भागीदारों के बीच व्यापार के लिए गैर-शुल्क बाधाओं को कम कर सकते हैं।

- ***मूल्य श्रृंखला का विस्तार***

एक विपरीत शुल्क ढांचा तब सामने आता है जब तैयार उत्पादों पर आयात शुल्क पुर्जों/कच्चे माल की तुलना में कम होता है और यह स्थानीय विनिर्माण के लिए पुर्जों और अन्य सामान के आयात के बजाय तैयार माल के आयात को प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करता है। एफटीए के कारण एक नए प्रकार का विपरीत शुल्क भी उत्पन्न हुआ है जिसमें एफटीए भागीदार देश से आयातित तैयार माल पर शून्य या कम शुल्क है,लेकिन उत्पादन के पहले चरणों के उत्पाद जैसे कच्चे माल और गैर-एफटीए देशों से आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं पर उच्च शुल्क है। विपरीत शुल्क संरचना कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपनी उत्पादन सुविधाएं बंद करने और देश से निकलने के लिए मजबूर कर रही है। यह कच्चे माल, विशेष रूप से कृषि के कच्चे माल जिसका शुल्क अपेक्षाकृत अधिक होता है, के संयोजन के कारण भी हो सकता है। किसी संवेदनशील वस्तु को छोड़कर कच्चे माल के लिए कम शुल्क सुनिश्चित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। संवेदनशील वस्तुओं विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की और आजीविका से जुड़ी चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह विपरीत शुल्क संरचना का समाधान करने में भी मदद करेगा। साथ ही भारत को भी वैश्विक मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। यह भारत में निर्माण को बढ़ावा देकर मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करेगा।

- ***लोगों की आवाजाही***

भारतीय प्रवासी वह प्रमुख आधार बन सकते हैं, जिसके जरिये भारत-यूरोपीय संघ के संबंधों को और मजबूत किया जा सकता है। सेवाओं की आपूर्ति के लिए व्यक्ति की अस्थायी आवाजाही (मोड 4) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सेवाओं में व्यापार पर सामान्यीकृत समझौते के तहत सेवाओं में व्यापार के चार तरीकों में से एक है। इस तरह, यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापक व्यापार समझौते का उपयोग यूरोपीय संघ में भारतीयों के हितों को और मजबूती प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। जब भारत यूरोपीय संघ के साथ बातचीत कर रहा है, तो वह मोड 4 के लिए उदार प्रतिबद्धता के लिए अनुरोध कर सकता है, जिसमें आव्रजन नीतियों, वीजा आवश्यकताओं, पढ़ाई के बाद रुकने और सामाजिक सुरक्षा लाभों के संदर्भ में उच्च और निम्न कुशल दोनों तरह के श्रमिकों को शामिल किया गया है। इस सौदे का सभी विनियमित व्यवसायों के नियामकों को समर्थन करना चाहिए ताकि अधिक योग्यता वाले भारतीय पेशेवरों को मान्यता मिल सके। इसका अर्थ यह होगा कि पेशेवर कई परीक्षाओं/पाठ्यक्रमों में फिर से बैठे बिना यूरोपीय संघ में नौकरी करने में सक्षम होंगे। भारतीय पेशेवरों को नए अवसरों से ईयू में काम करने या दूरस्थ रूप से सेवाएं देने का लाभ मिलेगा। साथ ही यूरोपीय संघ की कंपनियां अधिक वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने में सक्षम होंगी।

- ***समान विनिमय***

चूंकि यूरोपीय संघ के शुल्क पहले से ही कम हैं ऐसे में एफटीए से होने वाले शुल्क उदारीकरण से ईयू को अधिक लाभ होगा। इसलिए व्यापार सौदा समान विनिमय के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इसमें एक ओर जहां हम ईयू को भारत के बड़े बाजार में पहुंच उपलब्ध कराएं, वहीं दूसरी ओर भारतीय विनिर्माताओं और तकनीकी भागीदारों की अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने के लिए ईयू से अधिक निवेश हो सकता है। भारत को भूमि अधिग्रहण, और अनुबंधों के प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों में निवेशकों के लिए एक सुगम राह तैयार करने के लिए सुधार के अपने प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है। ■

भारत का इंजीनियरिंग वस्तु क्षेत्र : अद्यतन स्थिति

इंजीनियरिंग क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय

इंजीनियरिंग वस्तु टिकाऊ उत्पाद हैं जिनका उपयोग उत्पादन और सेवा आपूर्ति दोनों प्रक्रियाओं में विभिन्न मुख्य क्षेत्रों में संयंत्र, मशीनरी और पार्ट्स के रूप में किया जाता है। इंजीनियरिंग सामान क्षेत्र में मुख्य रूप से धातु और धातु उत्पाद (लौह और अलौह सहित), विद्युत मशीनरी, औद्योगिक मशीनरी, निर्माण उपकरण, मशीन टूल्स, ऑटोमोबाइल और ऑटो पुर्जे शामिल हैं।

इस क्षेत्र को मुख्य रूप से `हेवी इंजीनियरिंग' और `लाइट इंजीनियरिंग' खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारी इंजीनियरिंग खंड बिजली, प्लास्टिक, निर्माण, धातु विज्ञान, कपड़ा, चीनी, रबड़, डेयरी, तेल और गैस, रिफाइनरियां आदि विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इंजीनियरिंग उद्योग में अनेक प्रकार की भारी मशीनरी, विद्युत उपकरण, निर्माण उपकरण, खनन उपकरण, रक्षा उपकरण, मशीन टूल्स, ऑटोमोबाइल और ऑटो पुर्जे शामिल हैं। हल्के इंजीनियरिंग खंड द्वारा छोटे हिस्सों जैसे बेयरिंग, कास्टिंग, फास्टनर आदि की पूर्ति की जाती है और अक्सर भारी इंजीनियरिंग उद्योग द्वारा इनपुट (किसी वस्तु में दूसरी वस्तु डालना) के तौर पर इन सामानों का उपयोग किया जाता है।

उत्पादन परिदृश्य

इंजीनियरिंग वस्तु क्षेत्र भारत के सबसे बड़े और सबसे विविध औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 में इंजीनियरिंग वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य ₹39.0 लाख करोड़ आंका गया। 2011-12 से 2019-20 के दौरान इस क्षेत्र के उत्पादन में अनुमानित 7.5% की सीएजीआर दर्ज की गई।

इस क्षेत्र में धातु और धातु उत्पादों (लौह और अलौह धातुओं दोनों को मिलाकर) का निर्माण खंड सबसे बड़ा है और 2019-20 में इंजीनियरिंग सामान क्षेत्र के कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 47.3% की रही। इसके बाद परिवहन उपकरण (29.1% हिस्सेदारी), मशीनरी और उपकरण (14.2%) और विद्युत उपकरण (9.4%) का निर्माण खंड रहा।

भारत में इंजीनियरिंग वस्तुओं का खंड-वार उत्पादन

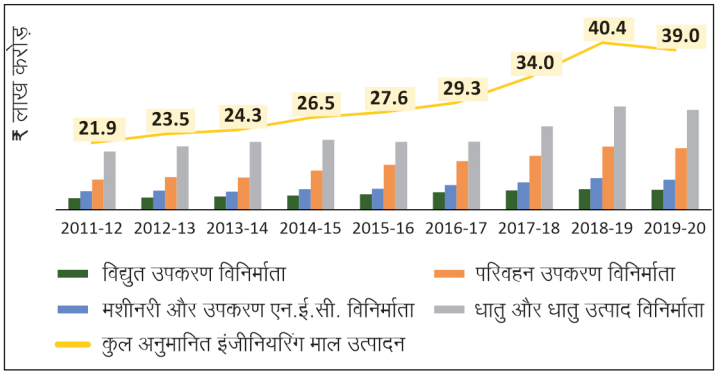

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; इंडिया एक्ज़िम बैंक अनुसंधान

भारत में इस क्षेत्र के समग्र उत्पादन परिदृश्य का अनुमान पूंजीगत वस्तुओं के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के उतार-चढ़ाव से भी लगाया जा सकता है। 2019-20 के दौरान भारत में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के आईआईपी में (-) 13.9% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। अगले वर्ष में विकास की गति और रुक गई। कोविड -19 के कारण आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के चलते 2020-21 के दौरान इस क्षेत्र (इंजीनियरिंग वस्तु क्षेत्र) के आईआईपी में (-) 18.6% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद, वित्तीय वर्ष 2022 में पूंजीगत वस्तुओं के लिए आईआईपी में लगातार सुधार हुआ और 2021-22 के दौरान कम आधार के साथ 17% की वर्ष-दर- वर्ष वृद्धि दर्ज की गई

निर्यात परिदृश्य

इंजीनियरिंग वस्तु क्षेत्र के 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन में से अनुमानित तौर पर लगभग 21.3% वस्तुओं का निर्यात किया गया। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत के इंजीनियरिंग निर्यात का मूल्य 112.1 बिलियन यूएस डॉलर रहा। यह भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य 107.3 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक रहा और इस दौरान वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर 46.1% दर्ज की गई। भारत के समग्र निर्यात के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2021-22 में भारत से कुल व्यापारिक निर्यात में इंजीनियरिंग वस्तुओं की 26.7% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही।

प्रमुख उत्पाद और बाजार

वित्तीय वर्ष 2022 में भारत के कुल इंजीनियरिंग निर्यात में लोहा व इस्पात और इनके (लोहा व इस्पात के) उत्पादों के निर्यात का कुल मिलाकर लगभग 28.3% योगदान रहा। इसके बाद औद्योगिक मशीनरी (22.0%); ऑटोमोबाइल और ऑटो पुर्जे (18.2%); अलौह धातु और उत्पाद (13.8%); और विद्युत मशीनरी (9.3%) व अन्य का स्थान रहा। इंजीनियरिंग वस्तुओं के विभिन्न खंडों में, भारत के अलौह धातु व उनके उत्पादों के निर्यात में वित्तीय वर्ष 2022 में 72.2% की उच्चतम वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। जबकि लौह और इस्पात व उसके उत्पादों के निर्यात में भी वर्ष के दौरान 69.6% की उल्लेखनीय वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, कुछ प्रमुख हाईटेक इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे ऑटोमोबाइल और ऑटो पुर्जे, औद्योगिक मशीनरी और इलेक्ट्रिकल मशीनरी के निर्यात में भी वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान क्रमशः 44.6%, 40.8% और 27.6% की मजबूत वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्ज की।

निर्यात बाजारों के संदर्भ में, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की इंजीनियरिंग वस्तुओं का सबसे बड़ा आयातक है और वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान कुल इंजीनियरिंग निर्यातों में इसकी हिस्सेदारी 15.5% की रही। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, अन्य शीर्ष आयातकों में यूएई (5% की हिस्सेदारी), चीन (4.9%), इटली (3.7%), जर्मनी (3.4%) नेपाल (3.1%) और अन्य शामिल रहे।

भारत सरकार ने हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सहयोग करने और बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं। इन पहलों में ऑटोमोबाइल और ऑटो पुर्जों के लिए पीएलआई योजना; उन्नत रसायन विज्ञान सेल (एसीसी) बैटरी निर्माण के लिए पीएलआई योजना; पूंजीगत वस्तुओं के लिए स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (समर्थ) योजना; और फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम II) योजना आदि शामिल हैं। इनसे इस क्षेत्र को शुभ संकेत मिलने की उम्मीद है जिससे आगामी वर्षों में निर्यात को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। ■

इंडिया एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं

इंडिया एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। ताकि इन ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए उन देशों के क्रेता भारत से विकासपरक तथा बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ हो सकें। इंडिया एक्ज़िम बैंक की इन ऋण-व्यवस्थाओं को भारत सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त होता है। इनके अंतर्गत इंडिया एक्ज़िम बैंक सामानों के नौवहन पर भारतीय निर्यातकों को अनुबंध मूल्य के 100% की प्रतिपूर्ति करता है। बशर्ते, कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के कम से कम 75% वस्तु तथा वस्तु एवं सेवाओं का स्रोत भारत हो। इन ऋण-व्यवस्थाओं ने उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता को प्रदर्शित करने में मदद की है। साथ ही ये ऋण-व्यवस्थाएं हाल के वर्षों में, विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों में एक माहौल बनाने में भी मददगार हुई हैं। इन ऋण-व्यवस्थाओं ने भारत के राजनीतिक, रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने के साथ ही लाभ-प्राप्त देशों में भारत के प्रति राजनीतिक सद्भाव के विकास में भी मदद की है। ऋण-व्यवस्थाओं ने भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत को प्रदर्शित किया है। विकासशील देशों के भीतर मूलभूत ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण में योगदान देने की भारत की इच्छा को भी दर्शाया है। ऋण-व्यवस्थाओं ने प्राप्तकर्ता देशों के ऐसे बाजारों में जरूरी उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में भी मदद की है, जहां भारत की मौजूदगी नहीं है या न के बराबर है। इंडिया एक्ज़िम बैंक से भारतीय निर्यातक अपने माल के लिए उचित मूल्य का भुगतान हासिल कर सकते हैं। इसके लिए उन पर कोई गारंटी वगैरा भी नहीं देनी होती। नौवहन दस्तावेज संबंधित वार्तालाप या सेवाओं के प्रावधान के एवज में यह सुविधा दी जाती है। भारतीय निर्यातक वस्तुओं के नौवहन पर इंडिया एक्ज़िम बैंक से पूरा भुगतान ले सकते हैं। इसमें उन्हें क्रेता या क्रेता देश से जुड़े किसी जोखिम का सामना भी नहीं करना पड़ता।

ऋण-व्यवस्थाएं संप्रभु सरकारों या उनकी नामित एजेंसियों को प्रदान की जाती हैं। ताकि उन देशों में क्रेता वस्तुओं एवं सेवाओं का आस्थगित भुगतान शर्तों पर भारत से आयात कर सकें। बैंक द्वारा यथा 21 सितंबर, 2022 को अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों के 67 देशों को 32.31 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 310 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गईं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार की ऋण-व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात के संवर्धन, सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

श्री सरोज खुंटिया,
महाप्रबंधक
इंडिया एक्ज़िम बैंक,
ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 1, 7वीं मंज़िल, एड्जेसेंट रिंग रोड,
किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली 110023,
फोन : +91-11-24607700
ई-मेलः eximloc@eximbankindia.in
वेबसाइटः www.eximbankindia.in

दास्तान-ए-कामयाबी

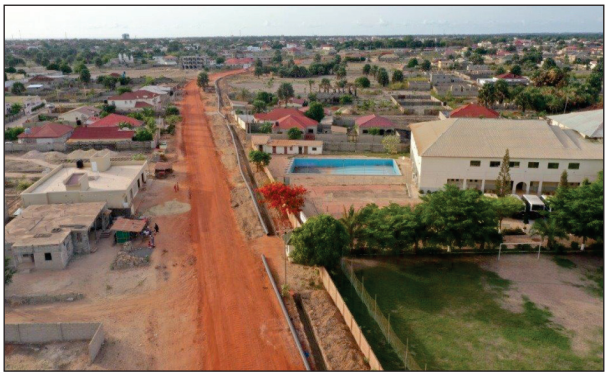

गांबिया सरकार को इंडिया एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार समर्थित 22.5 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था:

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के सहयोग से गांबिया सरकार को 22.5 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की थी। यह ऋण-व्यवस्था पानी के एस्बेस्टस पाइपों को हटाकर उनकी जगह यूपीवीसी पाइप लगाने के लिए प्रदान की गई थी। इस ऋण-व्यवस्था करार पर 29 अक्टूबर 2014 को हस्ताक्षर किए गए थे।

परियोजना : गांबिया के ग्रेटर बंजुल इलाके में पानी के एस्बेस्टस के पाइपों को हटाकर उनकी जगह यूपीवीसी के पाइप लगाना

कॉन्ट्रैक्ट पर शापूरजी पालोनजी एवं एसएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर जेवी द्वारा 5 जुलाई, 2016 को हस्ताक्षर किए गए और इसे ऋण-व्यवस्था में शामिल किया गया।

परियोजना के तहत गांबिया में जल-आपूर्ति पुनरुद्धार एवं विस्तार परियोजना और जल-आपूर्ति के लिए एस्बेस्टस पाइपों की जगह यूपीवीसी पाइप लगाने के लिए ईपीसी शामिल रहा।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार रहे :

- गांबिया के ग्रेटर बंजुल इलाके में पानी के सभी एस्बेस्टस पाइपों को हटाकर उनकी जगह यूपीवीसी के पाइप लगाना। ग्रेटर बंजुल इलाके की इन पाइपलाइनों से देश की एक तिहाई आबादी को पानी की आपूर्ति होती है। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने इन पाइपलाइनों को बदलने की सिफ़ारिश की थी।
- एस्बेस्टस पाइपों के लगातार फूटने की वजह से होने वाली पानी की बर्बादी को रोकना। गांबिया में ये पाइपलाइनें करीब 60 साल पुरानी हो चुकी हैं।

परियोजना की कुल लागत : 22.5 मिलियन यूएस डॉलर
परियोजना 11 अप्रैल, 2022 को सफलतापूर्वक पूरी हो गई।

तिमाही गतिविधियां

भारत–अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 17वां सीआईआई –एक्ज़िम बैंक कॉन्क्लेव

परियोजना भागीदारी पर 17वें सीआईआई-एक्ज़िम बैंक कॉन्क्लेव में 19 जुलाई, 2022 को "सुदृढ़ अफ्रीका का निर्माणः भारत का बढ़ता सहयोग" विषय पर इंडिया एक्ज़िम बैंक के शोध प्रकाशन का विमोचन किया गया। इस दौरान भारत के माननीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल, मॉरीशस के माननीय उप राष्ट्रपति श्री मैरी साइरिल एडी बोइसीज़ॉन, जीओएसके, गाम्बिया के माननीय उप राष्ट्रपति श्री बदारा ए. जोफ़, दक्षिण सूडान के माननीय उप राष्ट्रपति डॉ. जेम्स वानी इग्गा, ज़ाम्बिया की माननीय उप राष्ट्रपति सुश्री डब्ल्यू. के. मुटाले नलुमैंगो, नामीबिया की माननीय उप प्रधानमंत्री और अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग मंत्री सुश्री नेतुम्बो नांदी न्दाइत्वा और कॉर्पोरेट जगत के वरिष्ठ अधिकारियों सहित इंडिया एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी उपस्थित रहीं।

इंडिया एक्ज़िम बैंक के इस शोध प्रकाशन में भारत और अफ्रीका के बीच मौजूद परस्पर व्यापार की अपार संभावनाओं का उल्लेख किया गया है। 2021 में भारत-अफ्रीका का कुल व्यापार 82.5 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार का यह अब तक का सर्वोच्च स्तर रहा है। शोध में बताया गया है कि भारत और अफ्रीका के बीच 48 बिलियन यूएस डॉलर के द्विपक्षीय निर्यात की संभावनाएं हैं। इंडिया एक्ज़िम बैंक के इस शोध प्रकाशन में अफ्रीका के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की वर्तमान स्थिति और आने वाले समय में दोनों क्षेत्रों से निर्यातों की संभावनाओं का अध्ययन किया गया है। साथ ही, पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका के विकास में भारत के बढ़े सहयोग को भी रेखांकित किया गया है। इसके अलावा, विशेष रूप से हाल में बदलते वैश्विक परिवेश को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा इस विकास भागीदारी को और बढ़ाने की ज़रूरत का भी उल्लेख किया गया है।

पालघर और रायगढ़ में इंडिया एक्ज़िम बैंक से सहायता प्राप्त सीएसआर परियोजनाओं का उद्घाटन

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने स्वदेश फाउंडेशन के सहयोग से अपनी सीएसआर पहल के तहत महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के सुधागढ़ ब्लॉक में दो `ड्रीम विलेज' का उद्घाटन किया। इंडिया एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी ने 15 अगस्त, 2022 को इस परियोजना का शुभारंभ किया। ड्रीम विलेज परियोजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास एक व्यक्तिगत शौचालय, घर पर नल के जरिये वहनीय पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और गांवों का समग्र विकास किया जाना सुनिश्चित करेगी।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने महाराष्ट्र दयानंद अस्पताल के सहयोग से महाराष्ट्र के पालघर जिले में आदिवासी बच्चों के लिए नियो नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) सुविधा का 15 अगस्त, 2022 को उद्घाटन किया। एनआईसीयू सुविधा पालघर और दहानू की आदिवासी आबादी के नवजातों की आवश्यकताओं को पूरा करने लिए तैयार की गई है। एनआईसीयू जनजातीय क्षेत्रों में सालाना 200 से अधिक नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

कानपुर और उत्तराखंड में इंडिया एक्ज़िम बैंक का लोकसंपर्क कार्यक्रम

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने 16 सितंबर, 2022 को कानपुर में एफआईईओ के साथ साझेदारी में `अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एमएसएमई के लिए अवसर' पर एक सेमिनार का आयोजन किया। लोकसंपर्क कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निर्यातकों और उद्यमियों ने भाग लिया। इसमें उन्हें उभरते सितारे और व्यापार सहायता कार्यक्रम समेत बैंक की नई पहलों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

इंडिया एक्ज़िम बैंक और एफआईईओ द्वारा `उत्तराखंड से निर्यात को बढ़ावा देने' पर एक सेमिनार का 26 अगस्त, 2022 को आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तराखंड के अनुकूल व्यवसाय परिवेश, बुनियादी ढांचे और मजबूत उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे राज्य सरकार व्यवसाय परिवेश और निर्यात को मजबूती प्रदान करने के लिए सकारात्मक है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने नई दिल्ली में आयोजित किया एक्ज़िम बाजार

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी (कपड़ा मंत्रालय) में `एक्ज़िम बाज़ार' के 9वें संस्करण का 3-6 सितंबर, 2022 तक आयोजन किया। माननीय सांसद (राज्यसभा), पद्म विभूषण डॉ. सोनल मानसिंह ने इंडिया एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी के साथ बाज़ार का उद्घाटन किया। इस दौरान वस्त्र मंत्रालय के सचिव श्री यू.पी. सिंह उपस्थित रहे। इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा आयोजित इस बाजार में न केवल देशभर के बल्कि पड़ोसी देशों के भी पारंपरिक और समकालीन कला एवं शिल्प उत्पाद प्रदर्शित किए गए ।

भारत सरकार की `पड़ोसी देश प्रथम' नीति के अनुरूप, पहली बार बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका के दस्तकारों को भी अपनी पारंपरिक कला के स्वरूपों के प्रदर्शन के लिए इसमें आमंत्रित किया गया।

इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा एक्ज़िम बाज़ार का आयोजन व्यक्तिगत स्तर पर काम करने वाले दस्तकारों के साथ-साथ सूक्ष्म और ग्रासरूट स्तर के उद्यमों के लिए व्यवसाय संभावनाएं बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रदर्शनी से दस्तकारों को अपने उत्पादों के लिए बाजार बढ़ाने और अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलती है। दस्तकारों का ग्राहकों से सीधे संपर्क स्थापित होता है और भविष्य में बिक्री के रास्ते खुलते हैं। साथ ही, उपभोक्ताओं की पसंद को समझने, उद्योग जगत से जुड़ी जानकारियां हासिल करने और नए रुझानों को जानने में भी मदद मिलती है। ■

देशों का अवलोकन

तुर्की

महामारी के दौरान तुर्की ने जी-20 समूह में अन्य अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन किया और 2020 में मंदी को नहीं आने दिया। देश ने 2021 में 11.1% की वृद्धि दर्ज की, जो मुख्य रूप से मजबूत निर्यात मांग और निजी खपत में क्रेडिट-ईंधन विस्तार से प्रेरित रही। उच्च मुद्रास्फीति की वजह से घरेलू आय में कमी के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में 3.3% की वृद्धि के साथ 2022 में आर्थिक विकास के मध्यम रहने की उम्मीद है। लीरा में अस्थिरता, मुद्रास्फीति को लेकर मौजूदा आशंकाएं, यूक्रेन युद्ध और कमजोर मौद्रिक नीति के बीच वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप 2022 में मुद्रास्फीति का स्तर उच्च बना रहेगा। इसका (मुद्रास्फीति स्तर का) वार्षिक औसत 73.7% रहेगा। आंतरिक और बाहरी असंतुलन, उच्च मुद्रास्फीति और अमेरिका व यूरो क्षेत्र में मौद्रिक नीति का सामान्यीकरण, सभी यूएस डॉलर के मुकाबले लीरा के मूल्यह्रास में योगदान दे सकते हैं। 2022 में लीरा का एक यूएस डॉलर के मुकाबले औसत मूल्य 16.3 रहने का अनुमान है, जो 2021 के 8.9 से कम है। उच्च वैश्विक ऊर्जा कीमतों और धीमी निर्यात वृद्धि के कारण 2022 में चालू खाता घाटा बढ़ने और इसके 3.6% रहने की उम्मीद है।

दक्षिण अफ्रीका

प्राकृतिक संसाधनों की संपदा और एक विविध औद्योगिक आधार से युक्त दक्षिण अफ्रीका, उप-सहारा अफ्रीका की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था है। 2021 में 4.9% की वृद्धि के बाद 2022 में दक्षिण अफ्रीका की वास्तविक जीडीपी में 1.9% तक की कमी की आशंका है। इसका कारण वैश्विक मंदी के साथ-साथ बिजली की कमी जैसी घरेलू मोर्चे पर उत्पन्न आपूर्ति संबंधी बाधाएं हैं। तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी, बिजली दरों में भारी वृद्धि और वैश्विक रसद की ऊंची लागत के कारण, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के 2022 में बढ़कर पांच साल के उच्च स्तर 6.4% पर पहुंचने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड के गिरने और 2021 में एक यूएस डॉलर के मुकाबले 14.8 की कीमत से घटकर वर्ष 2022 में इसका मूल्य 15.8 होने की उम्मीद है। इसका कारण रैंड की वैश्विक नजरिये में प्रतिकूल बदलावों जैसे अमेरिका की मौद्रिक सख्ती और चीन में धीमी वृद्धि के प्रति संवेदनशीलता है। चालू खाते में 2021 में लगातार दूसरी बार अधिशेष दर्ज किया गया, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.7% रहा, लेकिन 2022 में इसके घाटे में बदलने और जीडीपी के 1.2% पर रहने की उम्मीद है। इसका कारण तेल मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ खाद्य और उर्वरक की उच्च कीमतें हैं, जिनमें रूस-यूक्रेन युद्ध से बढ़ोतरी हुई है और इससे आयात बढ़ा है। निर्यात को मजबूत खनिज कीमतों से सहारा मिलने की संभावना है, लेकिन इसमें अवसंरचना संबंधी बाधाएं बड़ी रुकावट हैं।

ब्राज़ील

2020 में 3.9% की गिरावट झेलने वाली ब्राजील की अर्थव्यवस्था दुनिया के कोविड-19 महामारी से उबरने के बीच 2021 में 4.6% बढ़ी। 2023 में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेज मंदी, उच्च (यद्यपि घटती) घरेलू ब्याज दरों और अभी भी उच्च मुद्रास्फीति के संयोजन से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2022 में 2% से घटकर अगले वर्ष 0.3% रहने की उम्मीद है। रूस-यूक्रेन संघर्ष की अवधि से बनी अनिश्चितता के कारण कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी और कमजोर राजकोषीय नीति से घरेलू मुद्रास्फीति पर उच्च दबाव बने रहने की उम्मीद है, क्योंकि मुद्रास्फीति 2020 में औसतन 3.2% से बढ़कर 2021 में 8.3% हो गई। इसके 2022 में बढ़कर 10.2% होने की उम्मीद है। अमेरिका की मौद्रिक सख्ती और ब्राजील की चुनाव संबंधी अस्थिरता ने 2021 में रियाल को कमजोर किया। 2020 में एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रियाल की कीमत 5.16 थी, जो 2021 में घटकर एक यूएस डॉलर के मुकाबले 5.40 रह गई। 2023 में कमोडिटी की घटी कीमतें 2022 में लौह अयस्क, तेल और सोयाबीन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण व्यापार अधिशेष में हुई वृद्धि को नीचे ले आएंगी। इससे चालू खाता घाटा 2022 में जीडीपी के 0.4% से बढ़कर 2023 में जीडीपी के 0.9% पर पहुंच जाएगा। देश के संरचनात्मक व्यापार अधिशेष, मामूली विदेशी ऋण अनुपात, बेहतर आरक्षित निधि और अतीत की तुलना में कमजोर रियाल से ब्राजील की बाहरी स्थिति के लिए जोखिम में कमी की उम्मीद है।

चाड

वास्तविक जीडीपी की वृद्धि 2021 की अनुमानित 0.7% से बढ़कर 2022 में 2.5% होने की उम्मीद है। यह कोविड -19 महामारी के नकारात्मक प्रभाव और वैश्विक तौर पर तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद तेल उत्पादन में मामूली वृद्धि से एक उबरती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। कपास के उच्च उत्पादन, बाहरी मांग में बढ़ोतरी और उंची कीमतों से भी वृद्धि को गति मिलेगी। इस तरह वृद्धि के 2023 में 2.7% तक बढ़ने का अनुमान है। वैश्विक मुद्रास्फीति के दबावों को देखते हुए, चाड में मुद्रास्फीति 2022 में औसतन 5.2% रहने और कमोडिटी की कीमतों में गिरावट और घरेलू मुद्रा के सहयोग से कम होकर 4.8% पर रहने का अनुमान है। सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रांक के मूल्यह्रास से 2021 के अंत के एक यूएस डॉलर के मुकाबले 579.2 की कीमत से गिरकर 2022 के अंत में (एक यूएस डॉलर के मुकाबले) 588.3 की कीमत पर आ जाने की उम्मीद है। ईसीबी के नीतिगत दरों को सख्त करने से सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रांक को मजबूती मिलने और 2023 के अंत में एक यूएस डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत 570.4 रहने का अनुमान है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ चाड की निर्यात आय में सुधार की उम्मीद है। चालू खाता घाटा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2021 में जीडीपी के 7.9% से 2022 में 4% रहने और फिर 2023 में 4.8% तक बढ़ने की उम्मीद है, जो तेल निर्यात आय में हलचल को दर्शाता है। इस घाटे की पूर्ति मुख्यतः विभिन्न बाह्य पक्षों के नकदी समर्थन से होने की आशा है। ■

मुद्राओं की स्थिति

इंडोनेशियाई रुपिया

Rp दक्षिणपूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने महामारी की बाधाओं से उबरते हुए अच्छी वृद्धि दर्ज की है। कमोडिटी की मजबूत वैश्विक मांग से इसे लाभ हुआ है। इंडोनेशिया की आर्थिक वृद्धि दर 2022 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 5.44% हो गई जिसे वर्ष की शुरुआत में गतिशीलता प्रतिबंधों में ढील के बाद मजबूत निर्यात और खपत में हुए सुधार का सहारा मिला।

इंडोनेशिया के केंद्रीय बैंक ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मौद्रिक सख्ती का उपाय अपनाया और 2018 के बाद पहली बार 23 अगस्त, 2022 को अपनी बेंचमार्क ब्याज दर बढ़ाई। बैंक इंडोनेशिया ने सात दिन की रिवर्स रेपो दर 25 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ाकर 3.75% कर दी। रुपिये को स्थिर करने के इन उपायों ने निवेशकों को भी दुनिया के अधिक लचीले उभरते बाजारों में से एक इस बाजार को लेकर आशावान बने रहने का कारण दिया है। केंद्रीय बैंक के इस नीतिगत उपाय की घोषणा के बाद से यूएस डॉलर के मुकाबले इंडोनेशियाई रुपिया 14,790 से 14,938 के बीच के स्तर पर रहा है।

15 सितंबर, 2022 को यूएस डॉलर के मुकाबले इंडोनेशियाई रुपिया 14,895 पर बंद हुआ।

कनाडाई डॉलर

C$ बैंक ऑफ कनाडा ने आक्रामक रुख अपनाते हुए ब्याज दरें उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दी हैं। 07 सितंबर को ब्याज दरों को 2.50% से बढ़ाकर 3.25% कर दिया है, जो 14 वर्षों का उच्चतम स्तर है। कनाडा ने ब्याज दरों में यह सख्ती मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने के उपाय के रूप में की है। दरें अब बैंक ऑफ कनाडा की तटस्थ सीमा से ऊपर हैं, जिसका अर्थ है कि लगभग दो दशकों में पहली बार मौद्रिक नीति से वृद्धि को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।

`स्टैटिस्टिक्स कनाडा" के आंकड़ों से स्पष्ट है कि अगस्त में कनाडाई अर्थव्यवस्था में कुल 39,700 नौकरियां गईं। जानकार विश्लेषकों का मानना है कि इनमें 15000 नौकरियां और जुड़ेंगी। बेरोजगारी दर बढ़कर 5.40% हो गई है। यह दर जुलाई में रिकॉर्ड निम्न स्तर 4.90% से बढ़कर 5.00% पर पहुंच गई। यूरोप में सर्दियों में तेल की मांग बढ़ने की उम्मीदों के मद्देनजर तेल की कीमतों में अच्छी वृद्धि हुई है, जो कनाडाई डॉलर को मजबूती प्रदान कर सकती है।

कनाडाई डॉलर में दो माह से भी अधिक समय बाद 13 सितंबर, 2022 को डॉलर के मुकाबले सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसका कारण था कि अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों में इस बात पर जोर दिया गया था कि फेडरल रिज़र्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी को आक्रामक रूप से जारी रखेगा।

मजबूत यूएस डॉलर के मुकाबले कनाडाई डॉलर उच्चतर रहा है और 15 सितंबर, 2022 को 1.3327 के स्तर पर बंद हुआ।

क्यूबाई पेसो

₱ भोजन और दवा की कमी, भीषण कटौती के साथ क्यूबा 1990 के दशक के बाद से अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। क्यूबा में रह रहे लोगों के लिए 2020 के बाद से डॉलर की खरीद के लिए काला बाजार के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा क्यूबा के बाहर से सामान की खरीद के लिए आवश्यक मुद्रा के नुकसान को रोकने के लिए ट्रेडिंग कंपनियों पर रोक लगा दी गई। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सुधार उपायों की घोषणा के साथ आधिकारिक विनिमय दर 24 पेसो निर्धारित किए जाने के बाद, जनवरी 2021 में डॉलर की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। नई विनिमय दर ने लागत में उत्तरोत्तर वृद्धि की। 2021 के अंत तक मुद्रास्फीति दर 70 प्रतिशत तक पहुंच गई।

क्यूबाई पेसो 1990 के दशक के बाद से यूएस डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर स्थिति में है, क्योंकि सोवियत खंड के पतन के बाद से कम्युनिस्ट द्वीप अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पेसो के अवमूल्यन को रोकने की कोशिश कर रहे क्यूबा के केंद्रीय बैंक ने पिछले महीने राज्य विनिमय संस्थानों में यूएस डॉलर के लिए 120 पेसो की विनिमय दर पर कारोबार करना शुरू किया। अनौपचारिक बाजार में भी यही दर प्रचलित है।

नई इज़रायली शेकेल

₪ इज़रायल की वार्षिक मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास ने सभी पूर्वानुमानों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि मूल्य लाभ अक्टूबर 2008 के बाद से अपने सबसे तीव्र स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता बन गई है। ताजा फल, परिवहन और आवासन कीमतों में वृद्धि के कारण वार्षिक मुद्रास्फीति जून की 4.40% से बढ़कर जुलाई में 5.20% हो गई और अभी भी लक्ष्य से अधिक है। हालांकि मुद्रास्फीति अगस्त में गिरकर 4.60% पर आई, लेकिन यह अभी भी 1-3% के लक्ष्य सीमा से ऊपर बनी हुई है।

केंद्रीय बैंक ने सख्ती जारी रखते हुए अगस्त में अपनी प्रमुख दर को 1.25% से बढ़ाकर 2.00% कर दिया। केंद्रीय बैंक ने अप्रैल में यह कड़ाई बरतनी शुरू की, जब पहली बार नीति निर्माताओं ने दर में 0.10% की वृद्धि की। यह दर का कोविड-19 महामारी की शुरुआत में सर्वकालिक निम्न स्तर था। दरों पर नीतिगत निर्णय के बाद दिन के कारोबार के दौरान शेकल डालर के मुकाबले मोटे तौर पर 3.28 पर स्थिर रही। इसके बाद, मुख्य रूप से यूएस डॉलर की मजबूती के कारण मुद्रा में गिरावट की प्रवृत्ति रही है। 15 सितंबर, 2022 को यूएस डॉलर के मुकाबले शेकल 3.4356 पर बंद हुई।

आई2यू2 जैसी बहुपक्षीय साझेदारी - जिसमें भारत, इज़रायल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं - में एक नीली अर्थव्यवस्था योजना पासा पलटने वाली हो सकती है। यह महासागर शासन के लिए एक उभरती हुई अवधारणा है जिसमें पर्यावरणीय रूप से वहनीय तरीकों से महासागरों की आर्थिक क्षमताओं का उपयोग किया जाता है। खाद्य सुरक्षा, यूक्रेन संकट और एक संयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना जैसे विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर, आई2यू2 में वैश्विक स्तर पर बड़ी छलांग लगाने की क्षमता है। ■

एक्ज़िम मित्र

भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने और भारतीय उद्यमियों के बीच व्यापार वित्त, ऋण बीमा और व्यापार से जुड़ी अन्य जानकारियों के प्रसार की विषमता को दूर करने के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक ने एक पोर्टल तैयार किया है। इसके मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं। निर्यातों के लिए ऋण की उपलब्धता के संबंध में जानकारी मुहैया कराना और व्यापार से संबंधित सूचनाएं प्रदान करना। एक्ज़िम मित्र के जरिए इस तरह के प्रयास करना, जिनसे भारतीय उद्यमियों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी जिज्ञासाओं का समाधान हो। इनमें से कुछ नीचे दी गई हैं:

सऊदी अरब से नई दिल्ली हस्तांतरित किए गए टेलीविजन पर लगाए गए सीमा शुल्क के बारे में जानकारी

एक्जिम मित्र पोर्टल पर `निर्यात-आयात की जानकारी' के तहत सीमा शुल्क कैलकुलेटर दिया गया है। इस पेज पर "आयात व्यापार संबंधी निर्देश" बटन पर क्लिक करने पर आप एक दूसरी वेबसाइट पर पहुंचेंगे। यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की वेबसाइट है। यहां आपको सीटीएच कॉलम में अपना एचएस कोड दर्ज करना है। उत्पाद के मूल देश का चयन करना है और सर्च बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने उत्पाद के एचएस कोड पर क्लिक कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक्जिम मित्र पोर्टल के अलग-अलग सेक्शन देख सकते हैं।

वसूली के लिए भेजे गए निर्यात बिलों के एवज में अग्रिम के बारे में सूचना

वसूली के लिए भेजे गए निर्यात बिलों पर कभी-कभी अग्रिम लेना भी संभव होता है। इस तरह के मामलों में बैंक द्वारा निर्यात बिलों की खरीद/डिस्काउंटिंग के एवज में बैंक द्वारा निर्यात बिल वसूली के आधार पर ही भेजे जाते हैं। इस तरह के बिलों पर अग्रिम अलग ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है, जिसे सामान्यतया `पोस्ट-शिपमेंट ऋण' कहा जाता है। वस्तुतः यह सुविधा पोस्ट-शिपमेंट का ही एक अन्य स्वरूप है। इसे बैंक द्वारा उन्हीं नियमों और शर्तों पर मंजूर किया जाता है जो निर्यात बिलों से संबंधित निगोशिएशन/खरीद/डिस्काउंट/ के लिए रहती हैं। हालांकि इस तरह के मामलों में 10% से 25% का मार्जिन भी निर्धारित किया जाता है। इस ऋण सुविधा पर देय ब्याज दर आदि के लिए वही नियम रहते हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रेता की निर्देशिका संबंधी सूचना

- एक्ज़िम मित्र पोर्टल पर `निर्यात-आयात की जानकारी' टैब में एक सेक्शन है `वैश्विक उत्पाद बाजार'। इस संबंध में इस सेक्शन पर जाकर जानकारी हासिल की जा सकती है।
- यहां सबसे पहले संबंधित व्यक्ति को निर्यात-आयात टैब पर क्लिक करना है। वहां उत्पाद का विवरण / एचएस कोड डालना होता है।
- इसके बाद जिस देश से आयात या निर्यात हो रहा है उसका चयन करना है। फिर "कंपनियां" टैब पर क्लिक करना है।

यहां कंपनियों से संबंधित जानकारियां मिल जाती हैं। लेकिन इसके लिए पहले संबंधित व्यक्ति को अपना अकाउंट बनाना जरूरी है।

क्रेता या क्रेता की निर्देशिका में कई चीजें देखी जा सकती हैं, जैसे...

- विभिन्न देशों की टेलीफोन डायरेक्ट्री (यलो पेजेज़ आदि)।
- डेटाबेस, जहां इस तरह की सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। उदाहरण के लिए, kompass.com, जहां 60 से अधिक देशों की 50 लाख से अधिक कंपनियों के बारे में तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं।
- जर्नल और पत्रिकाएं।
- इंडियन ट्रेड पोर्टल वेबसाइट पर विदेशी क्रेता सेक्शन है, वहां से भी जानकारी ली जा सकती है।
- हालांकि इस तरह की जानकारियों के साथ-साथ संबंधित व्यक्ति को संभावित क्रेताओं के बारे में समग्र अध्ययन भी अच्छी तरह कर लेना चाहिए।

क्या आपूर्तिकर्ता द्वारा दस्तावेजीकरण या ऐसी ही किसी त्रुटि के कारण लगाए गए विलंब शुल्क पर भी कोई जीएसटी लगता है?

अगर आपूर्तिकर्ता उचित दस्तावेज देने में विफल रहा है और इससे आप समय पर अपने सामानों को कस्टम्स से पास नहीं करा सके हैं और कोई इसका वहन करने को तैयार है, तो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची-II के क्रमांक संख्या 5 (ङ) के प्रावधान के अनुसार,

"...किसी कार्य से विरत होने की बाध्यता को मंजूरी देना या किसी कार्य या किसी स्थिति को सहन करना या किसी कार्य का करना", सब सेवा की आपूर्ति माना जाएगा। उपरोक्त केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7 (1) (घ) के तहत `आपूर्ति' के तहत वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति दोनों शामिल हैं, जैसा कि अनुसूची II में संदर्भित किया गया है।

लिहाज़ा आपूर्तिकर्ता की किसी कार्रवाई को सहन करने के कार्य को भी वास्तव में एक सेवा ही माना जाता है। इस तरह यह एकीकृत जीएसटी अधिनियम-2017 (आईजीएसटी) की धारा-5 के तहत करयोग्य है। इस तरह की सेवाओं पर जो आईजीएसटी लगता है, वह एकीकृत कर (दर) संबंधी 28 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 8/2017 के मुताबिक 18% है। इस तरह की सेवाओं के लिए स्थान का निर्धारण इन सेवाओं को प्राप्त करने के स्थान के आधार पर किया जाता है।

अगर विलंबित/क्षतिग्रस्त शिपमेंट प्राप्त होता है तो क्या ट्रांज़ैक्शन को अगले भुगतान-आदेश में अतिरिक्त भुगतान के रूप में समायोजित किया जा सकता है? फिर भले ही ट्रांज़ैक्शन वर्तमान में आवश्यक रूप से प्रतिबिंबित न हो?

अगर किसी विदेशी निर्यातक की ओर से शिपमेंट में विलंब होता है, तो किसी भी बकाया भुगतान को अगले भुगतान-आदेश में समायोजित किया जा सकता है। बस, इसमें असल इनवॉइस में दर्शाई गई राशि पर 5% की कटौती होगी। या फिर पिछला अगर कोई शिपमेंट देर से आया है, और उस पर कोई आर्थिक दंड लगाया गया है या कोई दावा लिया गया है, तो दोनों में जो राशि कम होगी, वह काटी जाएगी। ताकि चालान और बीओई के मूल्य का मिलान किया जा सके। अन्यथा, चालान मूल्य के 5% से अधिक नॉक ऑफ करने के लिए आरबीआई को उसकी मंजूरी के लिए संदर्भित कर सकते हैं।

आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था

वस्तु व्यापार

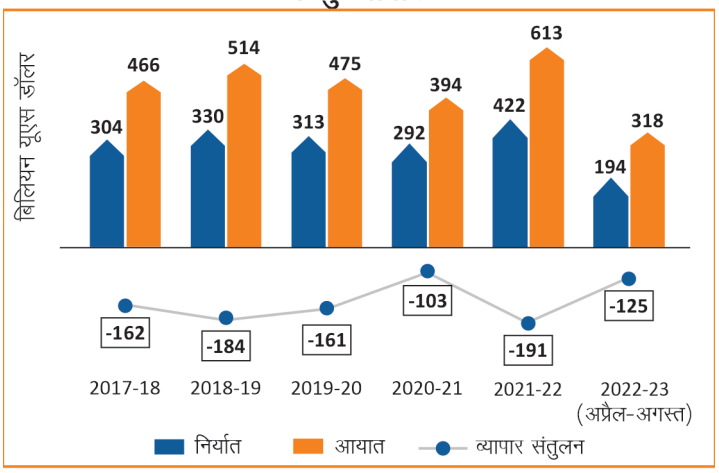

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सेवा व्यापार

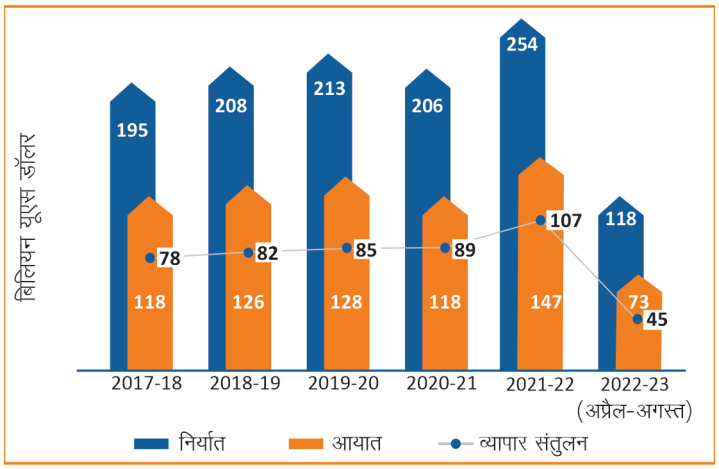

स्रोत: आरबीआई

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह

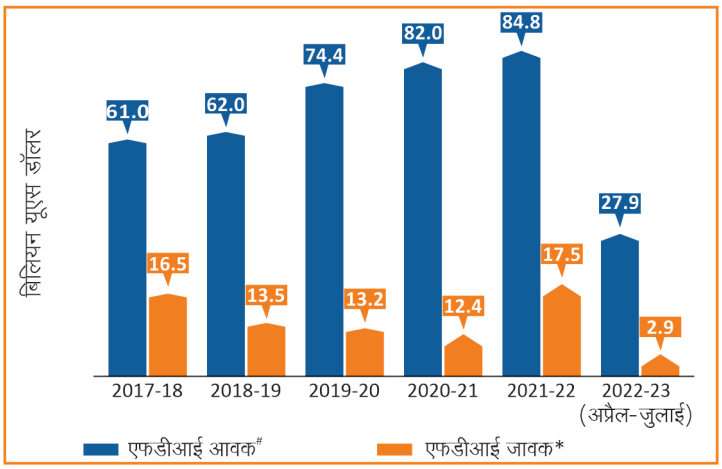

*नोट: *जावक एफडीआई में दिखाए गए आंकड़े वास्तविक हैं। इनमें इक्विटी, ऋण, और दी गई गारंटियां शामिल हैं।*
#आवक एफडीआई में इक्विटी, पुनर्निवेश से हुई आय और अन्य पूंजी शामिल है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

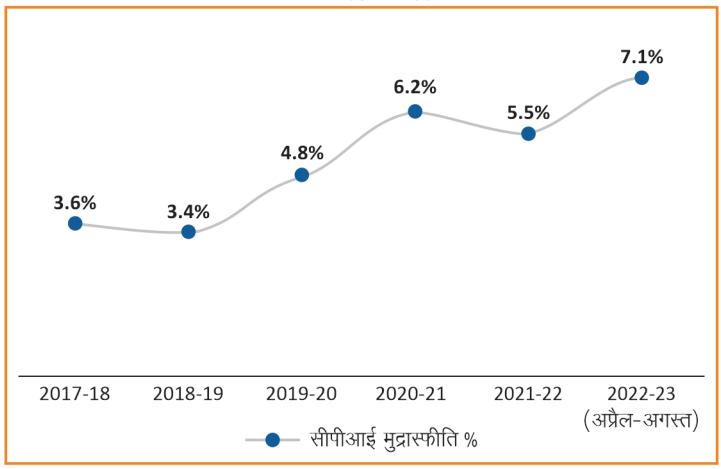

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चालू खाते का घाटा

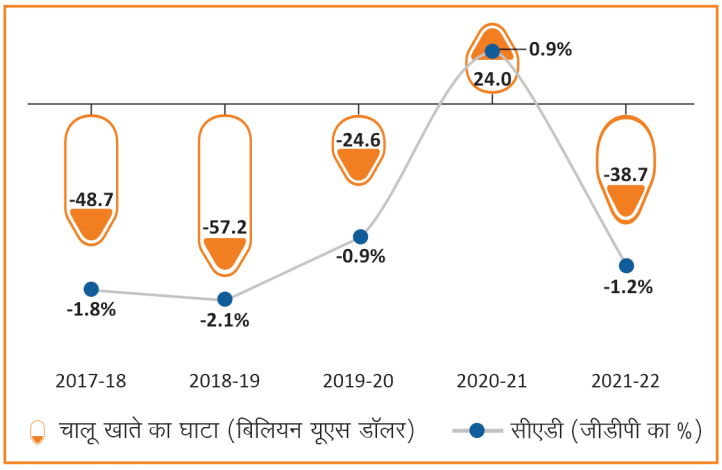

स्रोत: आरबीआई

क्षेत्रवार उत्पादन

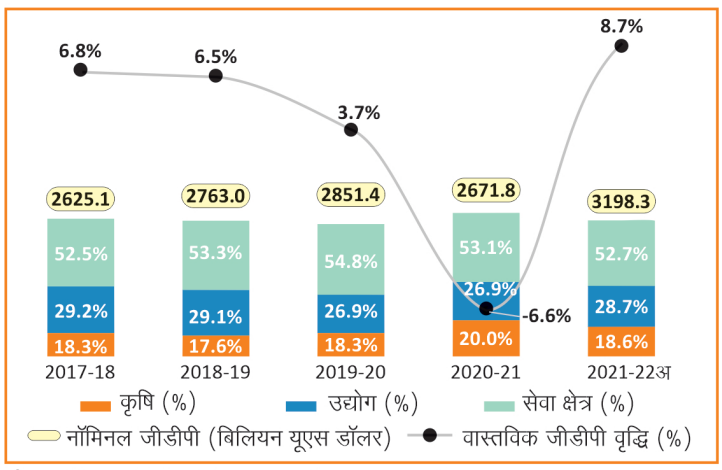

नोट: नॉमिनल जीडीपी (बिलियन यूएस डॉलर); अ-अनुमानित
स्रोत: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार